रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1986/श्रावण 11, 1908

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1986/SRAVANA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

का. आ. 2652.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग (पुनर्वास प्रभाग) के पुनर्वास (बंदोबस्त विंग) में बंदोबस्त अधिकारी श्री जे. एस. सहोता को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत सहायक अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से सहायक अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[संख्या -1(9)/वि. सैल/86-एस. एस.-II (ख)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 17th July, 1986

S.O. 2652.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) the Central Government hereby appoints Shri J. S. Sahota, Settlement Officer in the Rehabilitation Division (Settlement Wing) under the Ministry of Home Affairs, Department of Internal Security, as Assistant Custodian of Evacuee Property, in addition to his own duties, for the purpose of performing the functions assigned to such Assistant Custodian by or under the said Act, with immediate effect.

[No. 1(9)|86-Spl. Cell|SS. II(B)]

का. आ. 2653.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्वास प्रभाग के अधीन पुनर्वास प्रभाग (बंदोबस्त विंग) में बंदोबस्त अधिकारी श्री जे. एस. सहोता को उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा प्रबंध अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रबंध अधिकारी नियुक्त करती है।

[संख्या -1(9)86—विशेष सैल/एस. एस.-II (क)]

मु. असलम, उप सचिव

S.O. 2653.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri J. S. Sahota, Settle-

ment Officer in Rehabilitation Division (Settlement Wing) under the Ministry of Home Affairs, Department of Internal Security, as Managing Officer for the purpose of performing the functions assigned to a Managing Officer by or under the said Act, with Immediate effect.

[No. 1(9)|86-Spl. Cell|SS. II(A)]
M. ASLAM, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का. आ. 2654.—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 1 जनवरी 1974 के सा. का. नि. संख्या 63 तथा मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 22 फरवरी, 1975 के का. आ. संख्या 741 में निहित भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा :—

(i) सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे उच्च ओहदे के प्रत्येक सीमा-शुल्क अधिकारी;

(ii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता तथा उससे उच्च ओहदे के प्रत्येक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारी को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रवर्तन अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य-निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 178/5/84-स. स. (प्र.)]
ए. के. अग्निहोत्री, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2654.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the existing Orders of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. G.S.R. 63, dated the 1st January, 1974 and in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 741, dated the 22nd February, 1975, the Central Government hereby authorises :—

(i) every officer of Customs of the rank of an Assistant Collector of Customs and above;

(ii) every Central Excise Officer of the rank of an Assistant Collector of Central Excise and above.

to exercise the powers and discharge the duties of an officer of Enforcement under section 37 of the said Act.

[F. No. 178|5|84-TC(E)]
A. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का० आ० 2655.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री सी. एस. कल्याणसुन्दरम्, उप प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक को उसके द्वारा कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से लेकर औ 4 जनवरी, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 8/5/86-बी. ओ. -1]
एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2655.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 19 and sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri C. S. Kalyanasundaram, Deputy Managing Director, State Bank of India as the Managing Director of the State Bank of India for the period commencing with the date of his taking charge and ending with January 4, 1988.

[No. F. 8|5|86-BO. I]
M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1986

आदेश

का.आ. 2656:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 2 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त उप नियम के अनुसरण में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 355 तारीख 16 फरवरी, 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

2. यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में यदि कोई व्यक्ति कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 11वीं मंजिल, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) (क) सुसंगत भारतीय मानक तथा अन्य राष्ट्रीय मानकों का निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानकों को;

(ख) उत्पादों के परिशिष्ट-1 में दी गई न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अधीन रहते हुए संविदात्मक विनिर्देशों को रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना;

(3) इस आदेश के परिशिष्ट-2 में दिए गए रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1985 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों को लागू होगा।

(4) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित एक अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार सम्यक् रूप से निरीक्षण कर लिया गया है।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू-मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग द्वारा रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के उन नमूनों को लागू नहीं होगी जिनका पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य 500 रुपए से अधिक नहीं है।

4. इस अधिसूचना में रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों से इस आदेश की सारणी-I और II में दी गई मदें अभिप्रेत हैं।

सारणी-I

1. संश्लिष्ट इनेमल
2. ऊष्मारोधी वार्निशें वायु शुष्कम विदुमन प्रकार के।
3. संश्लिष्ट वार्निशें, फिनिसिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए)
4. इमल्शन रंगलेप (प्लास्टिक/ऐक्रलिक इमल्सन)

सारणी-II

1. सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अन्तर्गत संश्लिष्ट इनेमल को छोड़कर प्राइम, फिलर, अंडर कोटिंग तथा फिनिसिंग भी है।

2. संश्लिष्ट वार्निश फिनिसिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए तथा ऊष्मारोधी वार्निशों) हवा शुष्कम, विदुमन प्रकार के (अतिरिक्त सभी प्रकार की वार्निशों) प्राकृतिक लाख या संश्लिष्ट या दोनों से बनाई गई।

3. प्लास्टिक तथा ऐक्रलिक के अतिरिक्त सभी प्रकार के इमल्सन रंगलेप।

4. फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाइट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्षा सादी या रंग मिली हुई।

5. पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर
6. सूखे डिस्टेम्पर, चूने के रंग तथा सिमेंट रंग
7. सिमेंट रंगलेप
8. रंगलेप को मिलाने के लिए विलेयक
9. रंगलेप के लिए संश्लिष्ट लाख
10. रंगलेप के लिए संसाधित तेल और रंगलेप के लिए शुष्कम या अर्धशुष्कम तेल
11. विदुमिनिमस कोटिंग
12. एल्युमिनियम पेस्ट

परिशिष्ट-I

न्यूनतम अपेक्षाएं

1. सामान्य अपेक्षाएं

1.1 प्रत्येक ऊपर के डिब्बों पर निम्नलिखित से चिन्हित किया जाएगा।

(क) सामग्री का नाम और श्रेणी
(ख) विनिर्माता का नाम और/या व्यापार चिन्ह
(ग) फैक्ट्री कोड, यदि विनिर्माता की एक से अधिक विनिर्माण एकक है।
(घ) सामग्री की मात्रा
(ङ) विनिर्माता का बैच
(च) विनिर्माण का वर्ष तथा मास।

1.2 पैक में प्रारम्भिक डिब्बे इस तरह से पैक किए जाएंगे जिससे उनमें आपस में टकराव न हो।

1.3 डिब्बों की रिसाव परख और भीवन क्षमता की अपेक्षाएं ऐसी होंगी जो विनिर्माता द्वारा अधिकथित की जाएं।

1.4 बुल्ड डिब्बों (बैरल) या लकड़ी की पेटियों/गत्तेदार डिब्बों की जिनमें प्राइमरी डिब्बे पैक किए जाएंगे फिनिश अच्छी होगी और जोखिम सहन करने में पर्याप्त मजबूत होंगे।

1.5 फेंकने की पद्धति, उत्पाद की उत्तेजक प्रकृति, डिब्बे की अर्द्धावस्था और अन्य ऐसे संगत पहलुओं के बारे में उठाई धराई निर्देश विशेषतः अन्तरराष्ट्रीय रूप से मान्य सांकेतिक शब्दों में पैक के बाहरी और अंकित किए जाएंगे।

1.6 प्रत्येक परेषण पर प्रयोग के लिए निर्देश या तो प्रत्यक्ष रूप में डिब्बे पर अंकित होंगे या साहित्यिक रूप में होंगे।

2. परीक्षण :

2.1 निर्यात के लिए लौट पर निम्नानुसार परीक्षण लागू होगा। सारणी-1 की मदों के लिए उपाबंध (1) से (4) के अनुसार सारणी-2 की मदों के लिए संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुसार।

टिप्पणी : सारणी-2 की मदों के मामलों में, संगत राष्ट्रीय मानकों में विशिष्टताओं के लिए विनिर्देश क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार संविदा में वर्णित किए जाएंगे।

3. नमूना लेना

3.1 नमूने के रूप में चुने गए डिब्बों की संख्या प्रति लौट निम्नानुसार होगी।

नमूना लेने का मापदण्ड

लौट आकार (डिब्बों की संख्या)		नमूना लेने के लिए चुने गए डिब्बों की संख्या
तक	50	3
51 से	100	4
101 से	200	5
201 से	300	6
301 से	400	7
401 से	800	8
801 से	अधिक	10

टिप्पणी : —नमूना लेने के प्रयोजन के लिए लौट डिब्बों के नापों पर ध्यान दिए बिना विशेष फैक्ट्री कोड लिए हुए किसी विशेष वर्ग के उत्पाद के विनिर्माता का प्रत्येक बैच लगा होगा।

3.2 परीक्षण नमूनों की तैयारी : लौट से निकाले गए प्रत्येक नमूना का भार के लिए जहां कहीं लागू हो प्रति दस लीटर अलग अलग परीक्षण किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पाया जाता है तो उसी लौट में से लिए गए अलग नमूने मिला लिए जाएंगे और एक मिश्रित नमूना बन जाएगा और सामग्री विनिर्देश की सभी विशेषताओं के लिए मिश्रित नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

3.3 परीक्षण की प्रणाली : परीक्षण की प्रणाली निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी। ऐसे विनिर्दिष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में परीक्षण की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होगी।

संश्लिष्ट इनेमल के लिए परीक्षण

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे खुले डिब्बों में सामग्री लिवरिंग, अस्थिरता मादुक नहीं होगी विलोडित अवस्था पर ब्रश करने के लिए यह एक एकसार साफ और उचित उत्पाद के पश्चात् बनाएंगा। तथापि सामग्री को पतला करने के पश्चात् गाढ़ा छिड़काव होगा।

2. फिनिश : पैनल पर जब लागू हो जैसा कि निर्धारित हो, फिनिश चिकनी और चमकदार होगी, कंकरीलेपन, रंग के अलगाव या अन्य कोई सतही संदोष से मुक्त होगी।

3. पिसाई की सफाई : हैगमेन गेज से जब परीक्षित किया जाएगा यह 6 और कीथ. की रीडिंग देगा।

4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगी।

क्रम सं	विशेषताएं		अपेक्षाएं
(1)	(i) सुखाने का समय		
		(क) सतह शुष्क	अधिकतम 8 घण्टे
		(ख) कठोर शुष्क	अधिकतम 18 घण्टे
		(ग) टैंक मुक्त ड्राई	अधिकतम 24 घण्टे
	(ii) रंग		क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट के अनुसार (निकटतम मैच होना चाहिए)
	(iii) 30° सें ग्रे पर बी–4 फोर्ड कप में विस्कासिता		± 15 सेकेंड विनिर्दिष्ट
	(iv) प्रत्येक 10 लिटर पर भार		± 3 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
	(v) फ्लेश प्वाइंट		30° सें ग्रे. से कम नहीं
	(vi) खरोंच कठोरता परीक्षण		परीक्षण पास करने के लिए
	(vii) लचीलापन तथा आसंजन परीक्षण		परीक्षण पास करने के लिए
	(viii) निर्लेपन परीक्षण		—यथोक्त—

(5) पक्के रंग के लिए परीक्षण : नमूने परीक्षण पास करेंगे।

नोट : यह परीक्षण प्रत्येक परीक्षण पर करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक विनिर्माता सभी निरूपणों के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार यह परीक्षण करेगा।

उपाबंध — II

ऊष्मारोधी वार्निश के लिए परीक्षण हवाशुष्कम विटूमन प्रकार

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे खुले डिब्बों में सामग्री गहरे भूरे से काले रंग, तरल अवस्था में, त्वचा पर चिपकने से मुक्त, अवसाद तथा बाह्य पदार्थों से मुक्त होगी विलोडित अवस्था पर यह साफ, एक सार और एक रूप मिश्रण होगी।

2. कापर के साथ वार्निश की प्रतिक्रिया जब परीक्षण किया जाए तब कापर का रंग नहीं बदलेगा।

3. (क) 5000 वोल्ट/मिलीमीटर (न्यूनतम) कक्ष तापमान पर हवा में विद्युत क्षमता वोल्ट/मि मी (अधिकतम) में होगी।

(ख) पानी में निम्नजन के पश्चात् क्षमता प्रतिशत सामग्री 3000 वोल्ट/मि मी / न्यूनतम पर परीक्षण पास करेगी।

4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं का भी पालन करेगी :

क्रम सं०	विशेषताएं		अपेक्षाएं
(i)	प्रत्येक 10 लीटर पर भार		± 5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
(ii)	30. सें ग्रे पर बी–4 फोर्ड कप में विस्कासिता		± 15 सेकेंड विनिर्दिष्ट
(iii)	शुष्कन समय		
		(क) कड़ा सूखा	अधिकतम छह घन्टे
		(ख) टेक मुक्त सूखा	अधिकतम 24 घन्टे
(iv)	फलेश प्वाइंट		30 डिग्री सें ग्रे से कम नहीं
(v)	रंग		प्रत्येक नमूने के अनुसार (निकटतम मैच होगा)
(vi)	अवरोध या अवमिश्रण की क्षमता		100 प्रतिशत
(vii)	अवष्पशील पदार्थ प्रतिशत		± 3 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
(viii)	खानिज तेल का प्रतिरोध		परीक्षण पास करने के लिए
(ix)	थरमल एंड्यूरेंस परीक्षण		—यथोक्त—
(x)	लचीलापन तथा आसंजन परीक्षण		—यथोक्त—

उपाबंध-III

संश्लिष्ट वार्निश, फिनिशिंग के लिए परीक्षण (सामान्य प्रयोजन के लिए)

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे सुखे डिब्बों में सामग्री लिवरिंग या अस्थिरता के कोई भी चिन्ह नहीं दिखाएंगी। सामग्री साफ पारदर्शी तथा अवसाद तथा पपड़ी से मुक्त होगी। इसके संघटकों के क्रियाशील होने पर बराबर और सामरूप करने के लिए तेजी से बिखेरा जाएगा।

2. फिनिश : निर्धारित पैनल पर जब सामग्री लागू होगी, फिनिश बराबर और चमकदार होगी।

3. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगी :

क्रम सं०	विशेषताएं		अपेक्षाएं
(i)	सुखाने का समय		
		(क) सुखी सतह	छः घन्टे (अधिकतम)
		(ख) सख्त सूखा	18 घन्टे (अधिकतम)
		(ग) टैक मुक्त	24 घन्टे (अधिकतम)
(ii)	रंग		प्रति नमूने के अनुसार (एक निकटतम मैच होगा)
(iii)	फलैश प्वाइंट		30. सेंटीग्रेड से कम नहीं
(iv)	वाष्पशील पदार्थ प्रतिशत		60 प्रतिशत अधिकतम
(v)	30° सेंट्रीग्रेड पर विस्कासिता		1—3 स्टोक
(vi)	मूल्य अम्लमान		25.0 (अधिकतम)
(vii)	प्रति 10 लिटर भार		± 3प्रतिशत विनिर्दिष्ट
(viii)	अलकली के लिए प्रतिरोध		परीक्षण पास करना
(ix)	ऐसिड से प्रतिरोध		यथोक्त
(x)	पानी से प्रतिरोध		यथोक्त
(xi)	कठोर खरोंच परीक्षण		यथोक्त
(xii)	लचीलापन और आसंजन परीक्षण		यथोक्त
(xiii)	निर्लेपन परीक्षण		यथोक्त

उपाबंध—V

इमल्शन रंगलेप के लिए परीक्षण (प्लास्टिक/एक्रलिक इमल्सन)

1. प्रारम्भिक परीक्षण : ताजे सूखे डिब्बों में सामग्री डलों पपड़ी से मुक्त होगी, अधिक तलछट से पिण्ड बनाने कणिकायन, निवारण या रंग पृथक्करण से बाहर नहीं होगी और चिकनी और एक सार अवस्था के लिए निर्लेपन के साथ आसानी से बिखरी होगी। यह बदबूदार गंध से मुक्त होगी पतला करने के पश्चात गाढ़पन ब्रश या छिड़काव करने या रोलर प्रयोग करने के लिए गाढ़पन बराबर और एकसार होगा।

2. शुष्कन समय : रंग लेप के शुष्क सतह का समय 1 घन्टा (अधिकतम होगा) तथा पुनः कोटिंग का समय 4 घन्टे (अधिकतम होगा)

3. फिनिश : निर्धारित पैनल पर जब सामग्री लागू होगी, फिल्म की फिनिश, बराबर और अण्डे की सफेदी जैसी चमकदार होगी।

4. रंग : विदेशी क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के लिए निकटतम मैच होगा।

5. भार अपघर्षण से प्रतिरोध : 4000 ओसिलेशन के लिए रंगलेप फिल्म का परीक्षण पास करेगा।

6. प्रति 10 लिटर का भार : विनिर्दिष्ट भार के प्रत्येक 10 लिटर पर सहायता ± 5 प्रतिशत होगा।

7. हल्का सा पक्का : नमूने परीक्षण पास करेंगे।

8. क्षारकी से प्रतिरोध : नमूने परीक्षण पास करेंगे।

परिशिष्ट—II

[प्रस्ताव का पैरा (III) देखें]

[(निर्यात) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण (अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उप धारा (2) के खंड (घ) के अधीन बनाए गए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप)]

1. संक्षिप्त नाम : इन नियमों का संक्षिप्त नाम रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पाद (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1986 है।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (केन्द्रीय अधिनियम 1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचिन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद से अभिप्राय है।

सारणी—I

(i) संश्लिष्ट इनेमल
(ii) ऊष्मा रोधी वार्निशों शुष्क हवा, (बिटुमन प्रकार)
(iii) संश्लिष्ट वार्निशों, फिनिशिंग (सामन्य प्रयोजन)
(iv) इमलशन रंगलेप (प्लास्टिक/एक्रलिक इमल्सन)

सारणी-II

(i) संश्लिष्ट इनेमल के अतिरिक्त सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अन्तर्गत प्राइमर, अंडरकोटिंग फिनिशिंग भी है।

(ii) संश्लिष्ट वार्निशें फिनिशिंग (सामन्य प्रयोजन) और ऊष्मा-रोधी वार्निशों (हवा शुष्क, बिटुमन प्रकार) के अतिरिक्त सभी प्रकार की वार्निशों (कृत्रिम राल या संश्लिष्ट राल या दोनों से बनाई गई)

(iii) प्लास्टिक तथा एक्रलिक के अतिरिक्त सभी प्रकार के इमलसन रंगलेप।

(iv) फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाईट्रोसेल्यूलोज लेकर गाढ़ी या रंग मिली हुई प्रलाक्षा।

(v) पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर,

(vi) सूखे डिस्टेम्पर रंग तथा सिमेंट रंग,

(vii) सिमेंट रंगलेप,

(viii) रंगलेप को मिलाने के लिए विलेयक तथा पतली करने वाला पदार्थ।

(ix) रंगलेप के लिए संश्लिष्ट राल।

(x) रंगलेप के लिए संशोधित तेल या रंगलेप के लिए शुष्कम या अर्ध शुष्कम तेल।

(xi) बिटुमनी कोटिंग।

(xii) एल्यूमीनियम रंगलेप।

(घ) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार : निर्यात के लिए आशयित रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 केन्द्रीय अधिनियम (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरुप है।

(क) यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है।

(ख) अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट ढंग के अनुसार किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) इस प्रयोजन के लिए अभिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों की पर्याप्त व्यवस्था रखने वाले अनुमोदित विनिर्माण एकक के रंगलेप तथा संबंधित उत्पादों का निर्यात करने के लिए निर्यातकर्ता उप नियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों का परेषण अनुसूची—1 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किया गया है तथा परेषण प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(4) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर के परेषण के भेज जाने वाले कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी जबकि उप नियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माण के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उप नियम (1) के अधीन सूचना और उप नियम (2) के अधीन घोषणा यदि कोई हो के प्राप्त होने पर अभिकरण,

(क) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माता ने इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद को बनाने के लिए अनुसूची—1 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग

किया है तथा इस संबंध में परिषद/अभिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश यदि कोई हो का पालन किया है, रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों के परेषण को निर्यात करने के लिए तीन दिन के भीतर निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी कर देगा । जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां परेषण का ऐसा सत्यापन तथा निरीक्षण जो आवश्यक हो अभिकरण द्वारा किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है । अभिकरण परेषणों में से कुछ परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और यूनिटों द्वारा अपनाई गई उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण और पर्याप्तता को सत्यापित करने के लिए नियमित अन्तरालों पर यूनिट में भी जाएगा । यदि विनिर्माण यूनिटों में यह पाया जाता है कि उनमें विनिर्माण में किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण के उपायों और अभिकरण के अधिकारियों की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण नहीं है । ऐसे मामलों में यूनिट अपनी कमी को दूर करेगा और उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फिर से नया आवेदन देगा ।

(ख) ऐसी दशाओं में जिसमें निर्यातकर्ता ने उपनियम 3 (ख) के अधीन निर्यात करने की मांग की है अपना यह समाधान करने पर कि रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों का परेषण किए गए निरीक्षण/परीक्षण के आधार पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, निरीक्षण के सात दिन के भीतर रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों के परेषण का निर्यात करने के लिए निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यात के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा ।

(6) ऐसी दशा में जहां विनिर्माता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्यात करने के लिए निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उप नियम (5) (ख) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, वहां अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पैकेजों को परेषण इस ढंग से सीलबन्द करेगा कि सीलबंद पैकेजों में रद्दोबदल न की जा सके । परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण अभिकरण द्वारा सीलबन्द नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मामलों में, निर्यातकर्ता इन नियमों के नियम 8 के अधीन कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण :—

(क) या तो ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर;

या

(ख) ऐसे परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है परन्तु तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों ।

6. निरीक्षण फीस : इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता अभिकरण को प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क प्रत्येक एक सौ रुपए पर एक रुपया की दर से फीस देगा ।

7. अपील :—(1) नियम (4) के उप नियम (5) के अधीन प्रमाण पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषज्ञ पैनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे ।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

अनुसूची-I

[नियम 3 (क) देखें]

रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने अनुसूची-II में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग किया है ।

1. कच्ची सामग्री नियंत्रण :

(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की विशिष्टताओं को समाविष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) कच्ची सामग्री के स्वीकृत परेषणों के साथ या तो प्रदायकर्ता का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा या क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा । जिसमें विशिष्ट, प्रदायकर्ता के लिए क्रेता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक की प्रति जांच की जाएगी या क्रय की गई सामग्री का क्रेता द्वारा अपनी प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला/परख सदन के बाहर अधिकथित क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा ।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना अभिलिखित अन्वेषण के आधार पर विनिर्माता द्वारा अधिकथित किया जाएगा ।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण करने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री के पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियां यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाएंगी कि अस्वीकृत सामग्री का रंगलेप और संबद्ध उत्पादों के निर्माण में प्रयोग तो नहीं हो रहा है ।

(ङ) उपयुक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे गए अभिलेख वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त होंगे ।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) कच्ची सामग्री और मध्यम श्रेणी उत्पाद आदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देश विनिर्माता द्वारा कच्ची सामग्री और मध्यम श्रेणी उत्पाद की विशिष्टताओं के साथ अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित उत्पाद को नियंत्रित करने के लिए उपकरण तथा उपस्करों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रण के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे ।

3. उत्पाद नियंत्रण :

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों ।

(ख) प्रत्येक बैच से प्रतिनिधि नमूना लिया जाएगा सामूहिक नमूने को दो बराबर परख नमूनों में बांट दिया जाएगा ऐसा एक नमूना विनिर्माता द्वारा उत्पादन की अपेक्षाओं के लिए परीक्षित

लिया जाएगा तथा दूसरा नमूना उसके ब्योरे सहित कम से कम छः मास के लिए निर्देश नमूने के रूप में रखा जाएगा।

(ग) नमूना लेने और परीक्षण के बारे में अभिलेख इस संबंध में वस्तुतः प्रयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे।

(घ) अनुसूची II में निर्दिष्ट के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर होंगे।

4. परिरक्षण नियंत्रण :

विनिर्माता मध्यम तथा अन्तिम उत्पाद के परिरक्षण के लिए अपेक्षाएं अधिकथित करेगा।

5. पैकिंग नियंत्रण :

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के न्यूनतम विनिर्देशों की संतुष्टि की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे तथा उनका कठोरता से पालन किया जाएगा।

(ख) पैकिंग के संबंध में प्रयुक्त नियंत्रणों के लिए अभिलेख विनिर्माता द्वारा व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे।

अनुसूचि-II

नियंत्रण के स्तर

(क) सारणी-I में उल्लिखित उत्पाद के लिए

क्रम सं.	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	आवृत्ति
1	2	3	4	5
1.	गाढ़ापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
2.	शुष्कन समय	,,	,,	,,
3.	फिनिश	,,	,,	,,
4.	प्रति 10 लिटर भार	,,	,,	,,
5.	रंग	,,	,,	,,
6.	खरोंच कठोरता	,,	,,	,,
7.	लचीलापन तथा आसंजन	,,	,,	,,
8.	निलंपन परीक्षण	,,	,,	,,
9.	रंग का पक्कापन	,,	,,	,,
10.	अम्ल अंश	,,	,,	,,
11.	फ्लेश प्वाइंट	,,	,,	,,
12.	क्षारता परीक्षण	,,	,,	,,
13.	वाष्पशील पदार्थ	,,	,,	,,
14.	पानी का अवरोध	,,	,,	,,
15.	अम्ल का अवरोध	,,	,,	,,
16.	क्षार का अवरोध	,,	,,	,,
17.	पिसाई की सफाई	,,	,,	,,
18.	विस्फ मिता	,,	,,	,,
19.	नमक अवरोध	,,	,,	,,
20.	पानी की मात्रा (%)	,,	,,	,,
21.	गीलापन	,,	,,	,,
22.	वायु-विद्युत क्षमता परीक्षण	,,	,,	,,
23.	कापर एनेमल उष्मसह का अवरोध	,,	,,	,,
24.	कोवर सहित वार्निश का अवरोध	,,	,,	,,

(ख) सारणी-II में उल्लिखित उत्पाद के लिए :

(1) सभी प्रकार की संश्लिष्ट वार्निशों के अतिरिक्त, (फिनिशिंग के लिए संश्लिष्ट वार्निशों और ऊष्मारोधी वार्निशों, हवा शुष्कम, बिटुमन प्रकार के अलावा) सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप और एनेमल, प्लास्टिक और एक्रलिक लाइट्रो सैल्यूलोज लैकर, साफ या क्रोमवर्णित के अतिरिक्त सभी प्रकार के इमल्सन रंगलेप, जिसमें फिल्टर, सतहों के प्राइमर पेन्ट रंगलेप और पेस्ट डिस्टेम्पर भी सम्मिलित है ।

क्रम सं.	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	अनुपति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	गाढ़ापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हों
2.	शुष्कन समय	"	"	"	"
3.	फिनिश	"	"	"	"
4.	प्रतिलिटर/गैलन भार	"	"	"	"
5.	रंग	"	"	"	"
6.	खरोंच कठोरता	"	"	"	"
7.	लचीलापन तथा आमंजन	"	"	"	"
8.	अम्ल अंश/अम्लीयता	"	"	"	"
9.	क्षारता	"	"	"	"
10.	विद्युत प्रावलता	"	"	"	"
11.	द्रवण की दशा में संक्षारण से सुरक्षा	"	"	"	"
12.	वाष्पशील पदार्थ	"	"	"	"
13.	अविषाक्तता परख	"	"	"	"
14.	कालप्रभावजन	"	"	"	"
15.	तेल का प्रभाव	"	"	"	"
16.	फ्लेश प्वाइंट	"	"	"	"
17.	प्रावछन क्षमता	"	"	"	"
18.	अन्य परखें	"	"	"	"

(ii) शुष्क डिस्टेम्पर, चुने का रंग तथा सीमेंट रंग

1	2	3	4	5	6
1.	शुष्कन का समय (कठोरता तथा पुनः कोटिंग की विशेषताएं)	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हों
2.	फिनिश	"	"	"	"
3.	रंग	"	"	"	"
4.	लाइट की चमक	"	"	"	"
5.	जाली पर अवशेष	"	"	"	"
6.	शुष्क रगड़ने पर प्रतिरोध	"	"	"	"
7.	जल विकर्षन क्षमता	"	"	"	"
8.	मिश्रित रंगलेप की घट अवस्था	"	"	"	"
9.	गुणधर्म अनुरक्षण	"	"	"	"
10.	फैलाव क्षमता	"	"	"	"
11.	फैलाव का समय	"	"	"	"
12.	क्षमता	"	"	"	"
13.	अन्य परखें	"	"	"	"

टिप्पण : सीमेंट रंगलेप कार्बनिक योजना से मुक्त होना चाहिए ।

(iii) रंगलेप के लिए थिनर

1	2	3	4	5	6
1.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	अपेक्षितघनत्व	"	"	"	"
3.	आसवन क्षेत्र	"	"	"	"
4.	वाष्पीकरण का अवशेष	"	"	"	"
5.	कौरी बूटानोल मान	"	"	"	"
6.	हाईड्रोकार्बन विलेयकों के लिए सनिलिन प्वाइंट और मिश्रित एनिलिन प्वाइंट	"	"	"	"
7.	सक्रियित गंधक के लिए परख	"	"	"	"
8.	क्लोरीनित हाईड्रोकार्बन विलेयक पदार्थों तथा बेंजीन मुक्त के लिए परख	"	"	"	"
9.	अम्ल धुलाई परख	"	"	"	"
10.	हाईड्रोजन सल्फाईड तथा मिरकैपटैन के लिए परख	"	"	"	"
11.	सीसे से मुक्ति	"	"	"	"
12.	फलेश प्वाइंट	"	"	"	"
13.	विक्रेता तथा क्रेता के बीच तय हुई विशिष्ट परखें, यदि कोई हो	"	"	"	"

(iv) रंगलेप के लिए संश्लिष्ट राल :

1	2	3	4	5	6
1.	विस्कासिता	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	अम्ल मान	"	"	"	"
3.	एम. प्वाइंट (गलन बिन्दु)	"	"	"	"
4.	स्वच्छता	"	"	"	"
5.	अन्य परखें	"	"	"	"

(v) संसाधित तेल या रंगलेप के लिए शुष्कन या अशुष्कन तेलों के लिए रंगलेप

1	2	3	4	5	6
1.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	विशिष्ट घनत्व (या घनत्व)	"	"	"	"
3.	अम्ल मान	"	"	"	"
4.	अपवर्तन तालिका	"	"	"	"
5.	गलन (या सांद्रिकरण सें. ग्रेड बिन्दु)	"	"	"	"
6.	आयोडिन मान	"	"	"	"
7.	साबुन किरण मान	"	"	"	"
8.	अन्य परखें	"	"	"	"

(vi) बिटुमनसक कोटिंग

1	2	3	4	5	6
1.	विशिष्ट घनत्व	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	कोमलता बिन्दु	"	"	"	"
3.	क्षेपण परीक्षण	"	"	"	"
4.	छीलन परख	"	"	"	"
5.	आघात प्रबलता	"	"	"	"
6.	सुखाव परीक्षण	"	"	"	"
7.	राख मान	"	"	"	"
8.	अन्य परखें	"	"	"	"

(vii) एल्यूमिनियम पेस्ट

1	2	3	4	5	6
1.	एल्युमिनियम चूर्ण	इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	वर्कमान	"	"	"	"
3.	छानने पर अवशेष (150 माइक्रोन 75 माइक्रोन 53 मा. मा. छलनी)	"	"	"	"
4.	चिकनाई अंश	"	"	"	"
5.	फिनिश	"	"	"	"
6.	जमने की विशिष्टताएं	"	"	"	"
7.	वाष्पशील पदार्थ	"	"	"	"
8.	गुणधर्म अनुरक्षण	"	"	"	"
9.	कोपर तथा सीसे सहित कुल अशुद्धियां	"	"	"	"
10.	अन्य परखें	"	"	"	"

अनुसूची–III

[नियम 3 (ख) देखें]

1.1 रंगलेप और संबद्ध उत्पादों के परेषण को अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के अधीन किया जाएगा।

1.2 जब कि संविदात्मक विनिर्देशों में अन्यथा उल्लिखित न हो, नमूना मापदंड और निकाले गए नमूनों की संख्या अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

1.3 एक लौट में लिए गए प्रत्येक नमूने का प्रति 10 लीटर भार के लिए जहां कहीं भी लागू होगा अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा। यदि ये विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं तो उसी लौट से लिए गए अलग-अलग नमूनों को एक सम्मिलित नमूना बनाने के लिए इकट्ठा मिश्रित किया जाएगा। ऐसे एक परीक्षित नमूने का संगत विशिष्टताओं के लिए परीक्षण किया जाएगा और दूसरा कम से कम छः मास के लिए इसके ब्यौरे सहित निर्दिष्ट नमूने के रूप में रखा जाएगा।

1.4 यदि निर्यात संविदा में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो परीक्षण की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्दिष्टों के अनुसार होगी।

[फाइल सं. 6(5)/85-ई आई एंड ईपी]
एन.एस. हरिहरन, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd August, 1986

ORDER

S.O. 2656.—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that Paints and Allied Products should be subjected to quality control and inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. S.O. 355 dated 16th February, 1980 relaing to Paints and Allied Products except as respects, things done or omitted to be done, hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person who desire to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this Order in the Official Gazette of the Export Inspection Council of India, 11th Floor, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(i) To notify that Paints and Allied Products shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(ii) To recognise —

(a) relevant Indian Standard or any other national standard ; or standards of other bodies recognised by Export Inspection Council ;

(b) contractual specifications subject to the products satisfying the minimum requirements as set out in Appendix I—as the Standard Specifications for Paints and Allied Products

(iii) To specify the type of quality control and Inspection in accordance with the draft Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1986 as set out in Appendix II to this Order as the type of inspection which shall be applied to such Paints and Allied Products prior to their export ;

(iv) To prohibit the export of such Paints and Allied Products in the course of international trade unless the same are accompanied

by an Inspection Certificate for export issued by an Agency established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Paints and Allied Products have been duly inspected in accordance with the standard specifications and requirements of the Act.

3. Nothing in this Order shall apply to the export by sea, land or air of bonafide trade samples of Paints and Allied Products not exceeding Rs. 500|- only in Free on Board value to the prospective buyers.

4. In this notification "Paints and Allied Products" means items given in Tables I and II to this Order.

TABLE I

1. Synthetic enamels.
2. Insulating Varnishes (air drying, Bitumen type).
3. Synthetic Varnishes, finishing (General purposes).
4. Emulsion Paints, (Plastic|Acrylic Emulsion).

TABLE II

1. Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers, under-coating and finishing except synthetic enamels.
2. Varnishes of all types (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
3. Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.
4. Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including filler, primers or surfacers.
5. Paste paints and paste distempers.
6. Dry distempers, limecolours and cement colours.
7. Cement paints.
8. Thinners for paints.
9. Synthetic resin for paints.
10. Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints.
11. Bituminous coatings.
12. Aluminium paste.

APPENDIX I

MINIMUM REQUIREMENTS

1. General Requirements

1.1 Each primary container shall be marked with the following :—

(a) Name and class of the Material.

(b) Name of the manufacturer and|or trade mark.

(c) Factory code when a manufacturer has more than one manufacturing unit.

(d) Quantity of the material.

(e) Batch of manufacture.

(f) Month and year of manufacture.

1.2 The primary containers in a pack shall be so packed as to avoid collisions amongst them.

1.3 The requirements of leakproofness and seam strength of containers shall be as laid down by the manufacturer.

1.4 The bulk containers (barrels) or the wooden cases or corrugated boxes in which primary containers are packed shall be well finished and strong enough to withstand hazards.

1.5 Handling instructions preferably in internationally accepted symbolic codes in respect of method of slinging, inflammable nature of product, vertical position of container and such other relevant aspects shall be predominantly displayed on the outer packs.

1.6 Each consignment shall be accompanied by instructions for use either directly printed on the containers or in the form of literature.

2. TESTS

2.1 The tests which shall be applied against a lot for export shall be as below :—

For Table I items—As per Annexures (i) to (iv).
For Table II items—As per contractual requirements.

Note : In the case of Table II items, specifications against the characteristics in the relevant National Standards are to be mentioned in the contract as per buyer's requirements.

3. SAMPLING

3.1 The number of containers to be selected as samples per lot shall be as given below :—

SCALE OF SAMPLING

Lot Size (Number of containers)			Number of containers to be selected for sampling
Upto		50	3
51	to	100	4
101	to	200	5
201	to	300	6
301	to	400	7
401	to	800	8
801	to	above	10

Note A 'lot' for the purpose of sampling shall be each batch of manufacture of the particular class of product bearing the particular factory code irrespective of the container sizes.

3.2 Preparation of test, samples.

Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litres where applicable and if found conforming to the specified standard, the material of individual samples drawn from the same lot shall be blended to make a composite sample. Tests for all remaining characteristics shall be conducted on the composite sample.

3.3 Methods of tests.

Methods of tests shall be as stipulated in the export contract. In the absence of such specific stipulation methods of tests shall be as per the relevant Indian Standard Specification.

ANNEXURE I

TESTS FOR SYNTHETIC ENAMELS

1. Preliminary Examination

The material in a freshly opened container shall not show livering, instability and hard settling. On stirring it shall form a uniform, smooth and homogeneous product suitable for application by brushing. However, after thinning the material shall be of spraying consistency.

2. Finish

When applied on a panel as prescribed, the finish shall be smooth and glossy, free from grittings, separation of colour or any other surface imperfection.

3. Fineness of Grind

When tested with Hegman's gauge it shall give reading between 6 and 7.

4. The material shall also comply with the requirements glen below :—

S.No.	Characteristics	Requirements
(i)	Drying time	
	a) Surface dry	8 hours maximum
	(b) Hard dry	18 hours maximum
	(c) Tack free dry	24 hours maximum
(ii)	Colour	As specified by buyer (shall be a close match)
(iii)	Viscosity in B-4 Ford Cup at 30°C	Specified ± 15 seconds
(iv)	Weight per 10 litres	Specified 3%
(v)	Flash Point	Not below 30.C
(vi)	Scratch Hardness Test	To pass the test
(vii)	Flexibility and adhesion test	-do-
(viii)	Stripping test	-do-

5. Colour Eastness Test

The sample shall pass the test.

Note—This test need not be done on every consignment. Each manufacturer shall carry out this test at least once in every six months for each formulation.

ANNEXURE II

TESTS FOR INSULATING VARNISHES (AIR DRYING, BITUMEN TYPE)

1. Preliminary Examination

The material in a freshly opened container shall be dark brown to blackish in colour, liquid in state, free from skin formation, foreign matter and sediments. On stirring it shall become a smooth, uniform and homogeneous mixture.

2. Reaction of Varnish with Copper

The copper shall not change colour when tested.

3. (a) Electric strength in volts|m. in air at room temperature 5000 volts|mm. (Minimum)

(b) Electric strength after immersion in water

The material shall pass the test at 3000 volts|mm. (Min.)

4. The material shall also comply with the requirements given below :—

S.No.	Characteristics	Requirement
(i)	Weight per 10 litres	Specified ± 5%
(ii)	Viscosity in Ford Cup B-4 at 30°C.	Specified ± 15 seconds
(iii)	Drying time	
	(a) Hard dry	6 hours maximum
	(b) Tack free dry	24 hours maximum
(iv)	Flash point	Not below 30°C
(v)	Colour	As per sample (shall be a close match)
(vi)	Compatibility or dilution ability	100%
(vii)	Non-volatile matter %	Specified ± 3%
(viii)	Resistance to Mineral Oil	To pass the test
(ix)	Thermal endurance test	-do-
(x)	Flexibility and Adhesion test	-do-

ANNEXURE III

TESTS FOR SYNTHETIC VARNISHES, FINISHING (GENERAL PURPOSES)

1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall show no sign of livering or instability. The material shall be clear, trasnparent and free from sediment and skin. On stirring its components shall be rapidly dispersed to smooth and homogeneous.

2. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish shall be smooth and glossy.

3. The material shall also comply with the requirements given below:—

S.No.	Characteristic	Requirement
(i)	Drying time	
	(a) Surface dry	6 hours (max.)
	(b) Hard dry	18 hours (max.)
	(c) Tack free dry	24 hours (max.)
(ii)	Colour	As per sample (shall be a close match)
(iii)	Flash point	Not below 30°C
(iv)	Volatile matter %	60% Max.
(v)	Viscosity at 30° C	1-3-stokes
(vi)	Acid value	25.0 (Max.)
vii)	Weight per 10 litres	Specified ± 3%
(viii)	Resistance to Alkali	To pass the test
(ix)	Resistance to Acid	-do-
(x)	Resistance to Water	-do-
(xi)	Scratch hardness test	-do-
(xii)	Flexibility and Adhesion test	-do-
(xiii)	Stripping test	-do-

ANNEXURE IV

TESTS FOR EMULSION PAINTS (PLASTIC/ACRYLIC EMULSION)

1. Preliminary Examination.—In a freshly opened container, the material shall be free from lumps and skins, shall not exhibit excessive settling caking, granulation, livering or colour separation and shall be easily dispersed with a stirrer to a smooth homogeneous state. It shall be free from offensive odour. The consistency shall be smooth and uniform suitable for applying by brushing or spraying or by roller after thinning.

2. Drying Time.—The paint shall have a surface drying time of 1 hour (Max.) and recoating time of 4 hours (Max.).

3. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish of the film shall be smooth and matt or of egg shell gloss.

4. Colour.—It shall be a close match to standard specified by the foreign buyer.

5. Resistance to wet abrasion.—The paint film shall pass the test for 4000 oscillations.

6. Weight per 10 litres.—The tolerance on the specified weight per 10 litres shall be 5%.

7. Fastness to light.—The sample shall pass the test.

8. Resistance to alkali.—The sample shall pass the test.

APPENDIX II

[See paragraph (iii) of the proposal]

[Draft rules proposed to be made under clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963)].

1. Short title.—These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1986.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras.

(c) "Paints and Allied Products" means

TABLE I

(i) Synthetic enamels

(ii) Insulating varnishes (Air drying, Bitumin type)

(iii) Synthetic varnishes, finishing (General purposes)

(iv) Emulsion Paints (Plastic/Acrylic Emulsion).

TABLE II

(i) Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers, under coating and finishing except synthetic enamels.

(ii) Varnishes of all type (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumin type).

(iii) Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.

(iv) Nitrocellulose lecquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers.

(v) Paste paints and paste distempers.

(vi) Dry distempers, lime colours and cement colours.

(vii) Cement paints.

(viii) Thinners for paints.

(ix) Synthetic resin for paints.

(x) Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints.

(xi) Bituminous coatings.

(xii) Aluminium paste.

(d) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(e) "Schedules" means scheduled appended to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of paints and allied products for export shall be carried out with a view to seeing that the paints and allied products conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963) :

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Schedule I ;

Or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Schedule III.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Paints and Allied Products shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of Paints and Allied Products of a manufacturing unit approved as having adequate inprocess quality control by the Panel of Experts constituted by the Agency for this purposes, the exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Paints and Allied Products intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Schedule I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied on the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while the intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency :

(a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality control as laid down in Schedule I to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose and the manufacturer had followed the instructions if any, issued by the Council/Agency in this regard, shall within three days issue an inspection certificate for export of the consignment of Paints and Allied Products. In case where the manufacturer is not the exporter, such verification and inspection of consignment as necessary shall be carried out by the agency as to ensure that the above conditions have been complied with. The agency shall visit the units at regular intervals and conduct spot checks on some of the consignments to verify the adequacy of inprocess quality control adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adpoting the required quality control measures or recommendations of the officers of the Agency at any stage of manufacture the unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control. In such cases, the unit shall rectify deficiencies and apply afresh for the approval of inprocess quality control.

(b) In case where the exporter has sought export under sub-rule 3(b), on satisfying itself that the consignment of Paints and Allied Products conform to the standard specifications, on the basis of inspection/

testing carried out shall within seven days of inspection issue an inspection certificate for export of the consignment of Paints and Allied Products ;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall refuse to issue a certificate of inspection for export and shall communicate such refusal to the exporter within the said seven days alongwith the reasons therefor.

(6) In case where the manufacturer is not the exporter for export under sub-rule 5(a) or the consignment is inspected under sub-rule 5(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal under rule 8 of these rules.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either :—

(a) at the premises of the manufacturer of such products;

or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for inspection and testing exist therein.

6. Inspection Fee.—A fee at the rate of one rupee for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government ;

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials ;

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE I

[See under rule 3(a)]

Every manufacture of Paints and Allied Products shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product as laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule II.

(i) Raw Material Control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) The accepted consignments of raw materials shall either be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case counter checks shall be conducted atleast once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier or the purchased materials shall be regularly tested and inspected by the purchaser in own laboratory or in an outside laboratory/test house to ensure conformity with the laid down purchase specifications.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be laid down by the manufacturer based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials to ensure that the rejected materials are not used in the manufacture of Paints and Allied Products.

(e) Records in respect of the aforesaid controls regularly and systematically maintained by the manufacturer shall be adequate to verify the control actually exercised.

(ii) Process Control :

(a) Detailed process specification for different processes of manufacture including those for raw materials and intermediate products, if any, shall be laid down by the manufacturer alongwith the properties of raw materials and intermediate products.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Records shall be maintained by the manufacturer to verify that the controls actually exercised during the process of manufacture are adequate.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to the standard specification recognised under section 6 of the Act.

(b) A representative sample shall be drawn from each batch. The bulk sample shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested by the manufacturer for the requirements of products and the other preserved as referee samples alongwith its particulars for at least six months.

(c) Records in respect of sampling and tests shall be regularly and systematically maintained to verify the adequacy of the controls in this regard actually exercised.

(d) The minimum levels of control to check the product shall be as specified in Schedule II.

(iv) Preservation Control :

The requirements for preservation of intermediary and final products shall be laid down by the manufacturer.

(v) Packing Control :

(a) A packing specification shall be laid down with a view to satisfying minimum of the standard specifications recognised under section 6 of the Act and shall be rigidly implemented.

(b) Records in respect of the controls exercised in respect of packing shall be maintained by the manufacturer regularly and systematically.

SCHEDULE-II

LEVELS OF CONTROL

(a) For products mentioned in Table-I

S. No.	Requirement	Reference	No. of samples	Frequency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Consistency	Standard Specifications recognised for the purpose	One	Per Batch
2.	Drying Time	,,	,,	,,
3.	Finish	,,	,,	,,
4.	Weight per 10 litres	,,	,,	,,
5.	Colour	,,	,,	,,
6.	Scratch Hardness	,,	,,	,,
7.	Flexibility & Adhesion £	,,	,,	,,
8.	Stripping Test	,,	,,	,,
9.	Colour Fastness	,,	,,	,,
10.	Acid Value	,,	,,	,,
11.	Flash Point	,,	,,	,,
12.	Alkalinity Test	,,	,,	,,
13.	Volatile Matter	,,	,,	,,
14.	Resistance to Water	,,	,,	,,
15.	Resistance to Acid	,,	,,	,,
16.	Resistance to Alkali	,,	,,	,,
17.	Fineness of Grnd	,,	,,	,,
18.	Viscosity	,,	,,	,,
19.	Gloss Retention	,,	,,	,,
20.	Water Content (%)	,,	,,	,,
21.	Wet Opacity	,,	,,	,,
22.	Di-electric Strength Test	,,	,,	,,
23.	Resistance to Coil Enamel Insulation	,,	,,	,,
24.	Reaction of Varnish with Copper	,,	,,	,,

(b) For products mentjoned in Table-II

(i) Ready mixed paints and enamels of all types except synthetic, varnishes of all types (except synthetic varnishes for finishing) and insulating varnishes (air drying, bitumen type), Emulsion Points of all types except plastic and acrylic, Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers, paste Paint and paste distempers.

S. No	Requirement	Reference	No. of samples	Frequency	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consistency	Standard specification recognised for the purpose	One	Per Batch	Whenever applicable
2.	Drying time	,,	,,	,,	,,
3.	Finish	,,	,,	,,	,,
4.	Weight per litre/Gallon	,,	,,	,,	,,
5.	Colour	,,	,,	,,	,,
6.	Scratch hardness	,,	,,	,,	,,
7.	Flexibility & adhesion	,,	,,	,,	,,
8.	Acid valu/acidity	,,	,,	,,	,,
9.	Alkalinity	,,	,,	,,	,,
10.	Electric strength	,,	,,	,,	,,
11.	Protection against corrosion under conditions of condensation	,,	,,	,,	,,
12.	Volatile matter	,,	,,	,,	,,
13.	Toxicant availability test	,,	,,	,,	,,
14.	Ageing	,,	,,	,,	,,
15.	Effect of oil	,,	,,	,,	,,
16.	Flash Point	,,	,,	,,	,,
17.	Covering capacity	,,	,,	,,	,,
18.	Other tests	,,	,,	,,	,,

(ii) Dry distempers, lime colours and cement colours

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drying time (hardening and recoating properties)	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Wheneverapplicable
2.	Finish	,,	,,	,,	,,
3.	Colour	,,	,,	,,	,,
4.	Fastness to light	,,	,,	,,	,,
5.	Residue on sieve	,,	,,	,,	,,
6.	Resistance to dry rubbing	,,	,,	,,	,,
7.	Water Repellancy	,,	,,	,,	,,
8.	Pot life of mixed paint	,,	,,	,,	,,
9.	Keeping properties	,,	,,	,,	,,
10.	Spreading capacity	,,	,,	,,	,,
11.	Spreading time	,,	,,	,,	,,
12.	Capacity	,,	,,	,,	,,
13.	Other tests	,,	,,	,,	,,

Note : Cement paint shall be free from organic binders.

(iii) Thinners for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Colour	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	When ever applicable
2.	Relative density	,,	,,	,,	,,
3.	Distillation Range	,,	,,	,,	,,
4.	Residue on evaporation	,,	,,	,,	,,
5.	Kauri Butanol value	,,	,,	,,	,,
6.	Aniline point and mixed aniline point for hydrocarbon solvent	,,	,,	,,	,,
7.	Test for corrosive sulphur	,,	,,	,,	,,
8.	Test for freedom from chlorineted hydrocarbon solvents and benzene	,,	,,	,,	,,
9.	Acid wash test	,,	,,	,,	,,
10.	Test for hydrogen sulphide and mercapatans	,,	,,	,,	,,
11.	Freedom from lead	,,	,,	,,	,,
12.	Flash Point	,,	,,	,,	,,
13.	Specific test if any, as agreed between buyer and seller	,,	,,	,,	,,

(iv) Synthetic resin for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Viscosity	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	When ever applicable
2.	Acid value	,,	,,	,,	,,
3.	M. Pt.	,,	,,	,,	,,
4.	Clarity	,,	,,	,,	,,
5.	Other tests	,,	,,	,,	,,

(v) Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Colour	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever applicable
2.	Sp. Gr. (or density)	,,	,,	,,	,,
3.	Acid value	,,	,,	,,	,,
4.	Refractive Index	,,	,,	,,	,,
5.	Melting (or solidification) point oc.	,,	,,	,,	,,
6.	Iodine value	,,	,,	,,	,,
7.	Saponification value	,,	,,	,,	,,
8.	Other tests	,,	,,	,,	,,

(vi) Bituminous coatings

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Specific gravity	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever applicable
2.	Softening point	,,	,,	,,	,,
3.	Penetration test	,,	,,	,,	,,
4.	Peel test	,,	,,	,,	,,
5.	Impact strength	,,	,,	,,	,,
6.	Sag test	,,	,,	,,	,,
7.	Ash content	,,	,,	,,	,,
8.	Other tests	,,	,,	,,	,,

(vii) Aluminium pasts

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aluminium powder	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever applicable
2.	Leafing value	,,	,,	,,	,,
3.	Residue on sieves (150 micron, 75 Micron 53 micron I.S. Sieves)	,,	,,	,,	,,
4.	Grease content	,,	,,	,,	,,
5.	Finish	,,	,,	,,	,,
6.	Settling properties	,,	,,	,,	,,
7.	Volatile matter	,,	,,	,,	,,
8.	Keeping properties	,,	,,	,,	,,
9.	Total impurities including copper and lead	,,	,,	,,	,,
10.	Other tests	,,	,,	,,	,,

SCHEDULE III

[See under rule 3(b)]

1.1 The consignment of Paints and Allied Products shall be subject to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

1.2 Unless otherwise mentioned in the contractual specifications, the sampling criteria and the number of samples to be drawn shall be as per the minimum requirements notified under Section 6 of the Act.

1.3 Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 1 litre wherever applicable. If they are found to be conforming to the specified standard individual samples drawn from the same lot shall be blended together to make composite sample and then shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested for the relevant characteristics and the other preserved as referee sample alongwith its particulars for atleast six months.

1.4 If not otherwise specified in the export contract, methods of testing shall be as per relevant Indian Standards Specifications.

[F. No. 6(5)|85-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का. आ. 2657.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स भोपाल शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सेहोर (मध्य प्रदेश) -466003 में है, (पंजीकृत प्रमाण पत्र संख्या 1112/75) के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है ।

[संख्या 16/12/86-एम. -3]
आर. डी. मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2657.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M|s. Bhopal Sugar Industries Limited having its registered office at SEHORE (M.P.)—466003 under the said Act (certificate of Registration No.—1112|75).

[No. 16|12|86-M. III]
R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1986

का. आ. 2658.—सदस्य, वायदा बाजार आयोग, बम्बई के रूप में अपने बढे हुए कार्यकाल के पूरा होने पर श्री ए. एन. कोल्हाटकर, आई. आर. एम. (आई. टी.) ने 30 जून, 1986 के अपराह्न से आयोग में सदस्य के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

[सं. ए-12011/17/82-प्रशा. -II]
ओ. पी. खेत्रपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 8th July, 1986

S.O. 2658.—On the completion of his extended term as Member, Forward Markets Commission, Bombay, Shri A. N. Kolhatkar, I. R. S. (II), relinquished charge of the post of Member in the Commission on the afternoon of the 30th June, 1986.

[F. No. A-12011/17/82-Estt. II]
O. P. KHETRAPAL, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1986

का० आ० 2659.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2308 तारीख 15 मई, 1985 द्वारा, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 816.50 एकड़ (लगभग) या 330.42 हेक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 816.50 एकड़ (लगभग) या 330.42 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण :—1. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. राजस्व 1/86 तारीख 4-1-86 का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण :—2. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :—

"8. (1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना आक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आदेश सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशें और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाता ।"

टिप्पण : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची

उत्तर बुंदू ब्लाक

दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्र

जिला हजारीबाग (बिहार)

अर्जित की जाने वाली भूमि :
सभी अधिकार

क्रम सं	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
ब्लाक "क"						
1.	बसारिया	मांडू	38	हजारीबाग	179.00	भाग
2.	बुंदू	मांडू	39	,,	320.00	भाग
3.	टोंगी	मांडू	135	,,	224.00	भाग
ब्लाक "ख"						
4.	चोरधारा उर्फ (खर पतनगर)	रामगढ़	55	,,	93.50	भाग
		कुल क्षेत्र :			816.50 एकड़ (लगभग)	
		या			330.42 हैक्टर (लगभग)	

ब्लाक "क"

बसारिया ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

228, 229 (भाग), 30, 32 से 255, 256 (भाग), 257, 258 (भाग), 276 (भाग), 277 (भाग), 278 (भाग), 287 (भाग), 327 (भाग), और 432 (भाग)

बुंदू ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

55 (भाग), 59 (भाग), 60, 61 (भाग), 62 (भाग), 63 (भाग), 65 (भाग), 136 (भाग), 137 (भाग), 138 से 209, 210 (भाग), 211 (भाग), 212 (भाग), 213 से 221, 222 (भाग), 223 से 227, 228(भाग), 229 (भाग), 230, 231, 232, 233(भाग), 234 (भाग), 235 (भाग), 236 (भाग), 237 (भाग), 247 (भाग), 249 (भाग), 293 (भाग), 294 (भाग), 295 (भाग), 296, 297, 298 (भाग),

428 (भाग), 474 (भाग), 475 से 480, 481 (भाग), 482 से 500, 501 (भाग), 502 से 506, 507 (भाग), 508 से 558, 559 (भाग), 574(भाग), 575, 576 (भाग), 577 से 598, 599 (भाग), 604 (भाग) 605 (भाग), 606 (भाग), 607, 608, 609 (भाग), 610 से 614, 615 (भाग), 616 से 641, 642 (भाग), 649, 650, 654 और 655।

टोंगी ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

936 (भाग), 943 (भाग), 944, 945, 946 (भाग), 947 से 976, 977 (भाग), 978, 979, 980 (भाग), 981, 983 (भाग), 991 (भाग), 992, 993 (भाग), 994, 995, 996 (भाग) और 1025 (भाग)।

ब्लाक "ख"

चोरधारा उर्फ खरपतनगर ग्राम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं०

7 (भाग), 8 (भाग), 9 से 19, 21, 22, 23 और 24।

ब्लाक "क" का सीमा वर्णन :

क–ख रेखा, बसारिया ग्राम में, दामोदर नदी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है।

ख–ग रेखा, बुंदू ग्राम में, दामोदर नदी की पूर्वी सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है।

ग–घ रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट सं. 560 और 562 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, प्लाट सं. 576 से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन लापांगा ब्लाक विस्तार II की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

घ–ङ–च रेखा, बुंदू ग्राम में प्लाट सं० 576, 574, 576 से होकर, प्लाट सं. 642 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ और प्लाट सं. 642 से होकर जाती है और बुंदू और टोंगी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ–साथ जाती है (जो सिरका कोलियरी विस्तार के 102.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

च-छ रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं. 993 से होकर जाती है (जो सिरका कोलियरी विस्तार के 102.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है।

छ-ज रेखा, टोंगी और सिरका ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ–साथ जाती है)।

ज-झ रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं. 993 से होकर जाती है (जो सिरका कोलियरी विस्तार के 140.00 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अर्जित क्षेत्र की सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है)।

झ–ञ रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं० 993, 996, 993, 991 977, 980, 983, 1025, 946 से होकर जाती है।

ञ–क रेखा, टोंगी ग्राम में प्लाट सं. 946, 943 और 936 से होकर जाती है, बुंदू ग्राम में प्लाट सं. 615, 604, 609, 605, 606, 599, 507, 428, 501, 428, 474, 481, 474, 298, 295, 294, 293, 210, 211, 212, 222, 223, 249, 228, 247, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 235, 137, 136, 62, 63, 61, 65, 559, 55, 559, 55, 559 और 59 से होकर जाती है, फिर बसारिया ग्राम में 432, 256, 327, 256, 258, 256, 276, 277, 278, 287 और 229 से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

ब्लाक "ख"

ट–ठ रेखा, चोरधारा ग्राम में प्लाट सं. 8, 7 और 8 से होकर जाती है (जो लापांगा ब्लाक विस्तार के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ठ–ड रेखा, चोरधारा ग्राम में प्लाट सं. 26 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ जाती है (जो चोरधारा ब्लाक के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित क्षेत्र से मिलकर सम्मिलित सीमा बनाती है)।

ड–ढ–ट रेखा, चोरधारा ग्राम में दामोदर नदी की पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी सीमा के भाग के साथ–साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "ट" पर मिलती है।

[सं. 43019/33/84-सी ए]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 10th July, 1986

S.O.2659.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 3303 dated the 15th May, 1985 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 816.50 acres (approximately) or 330.42 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 816.50 acres (approximately) or 330.42 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1 :—The plan No. R-V/1/86 dated 4-1-86 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Ltd. (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2 :—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), which provides as follows —

"8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with a record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this act.

Note 3 :—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

NORTH BUNDU BLOCK

NORTH KARANPURA COALFIELD

DIST. HAZARIBAGH (BIHAR)

Lands to be acquired

All Rights

Serial number		Village	Thana	Thana number
Block 'A'	1.	Basaria	Mandu	38
	2.	Bundu	Mandu	39
	3.	Tongi	,,	135
Block 'B'	4.	Chordhara alias (Kharpatanagar)	Ramgarh	55

District	Area	Remarks
Hazaribagh	179.00	Part
,,	320.00	,,
,,	224.00	,,
,,	93.50	,,

Total area—816.50 acres (approximately)

Or 330.42 hectares (,,)

Block 'A'

Plot numbers to be acquired in village Basaria :—

228, 229 Part), 230, 232 to 255, 256(Part), 257, 258(Part), 276(Part), 277(Part), 278(Part), 287 (Part), 327(Part), and 432 (Part).

Plot numbers to be acquired in village Bundu :—

55(Part), 59(Part), 60, 61[Part), 62(Part), 63(Part), 65(Part), 136(Part), 137(Part), 138 to 209, 210(Part) 211)(Part) 212 (Part) 213 to 221, 222(Part), 223 to 227, 228(Part), 229(Part), 230, 231, 232, 233(Part), 234(Part), 235(Part), 236(Part), 237(Part), 247 (Part) 249(Part), 293(Part), 294(Part), 295(Part), 296, 297. 298(Part), 428(Part), 474(Part), 475 to 480, 481(Part), 482 to 500, 501(Part), 502 to 506, 507(Part), 508 to 558, 559(Part), 574(Part), 575, 576(Part), 577 to 598, 599(Part), 604(Part), 605(Part), 606 (Part), 607, 608, 609(Part), 610 to 614, 615(Part), 616 to 641, 642(Part), 649, 650, 654 and 655.

Plot numbers to be acquired in village Tongi :—

936 (part), 943(Part), 944, 945, 946(Part), 947 to 976, 977 (Part), 978, 979, 980(Part), 981, 983(Part), 991(Part), 992, 993(Part), 994, 995, 996(Part) and 1025(Part).

Block 'B'

Plot numbers to be acquired in Village Chordhara alias Kharapatnagar :

7(Part), 8(Part), 9 to 19, 21, 22, 23 and 24.

Boundary description of Block 'A'

A B	line passes along the northern boundary of Damodar river in village Basaria.
B–C	line passes along the part eastern boundary of Damodar river in village Bundu.
C–D	line passes along the northern boundary of plot numbers 560 and 562 through plot number 576 in village Bundu which forms part common boundary of Lapanga Block Extn. II U/s 7(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development Act, 1957).
D–E F	lines pass through plot numbers 576, 574, 576 along northern boundary of plot number 642 and through plot number 642 in village Bundu and along part common boundary of villages Bundu and Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 of Sirka Colliery Extn. for an area of 102.00 acres).
F–G	line passes through plot numbers 993 in village Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/s 9 (1) of Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 of Sirka colliery Extn. for an area of 102.00 acres).
G H	line passes along the part common boundary of villages Tongi and Sirka.
H–I	line passes through plot number 993 in village Tongi (which forms part common boundary of the area acquired U/s 9 (1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 of Sirka colliery Extn. III for an area of 140.00 acres).
I–J	line passes through plot numbers 993, 996, 993, 991, 977, 980, 983 1025, 946 in village Tongi.
J–A	line passes through plot numbers 946, 943 and 936 in village Tongi, through plot numbers 615, 604, 609, 605, 606, 599, 507, 428, 501, 428, 474, 481, 474, 298, 295, 294, 293, 210, 211, 212, 222, 223, 249, 228, 247, 228, 229, 233, 234, 236, 237, 235, 137, 136, 62, 63, 61, 65, 559, 55, 559, 55, 559 and 59 in village Bundu, then through plot numbers 432, 256, 327, 256, 258, 256, 276, 277, 278, 287 and 229 in village Basaria and meets at starting point 'A'.

Block–'B'

K–L	line passes through plot numbers 8, 7 and 8 in village Chordhara (which forms common boundary with the acquired U/s (9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 for Lapanga Block Extn.)

L-M lines passes along northern boundary of plot number 26 in village Chordhara [which forms common boundary with the area acquired U/s 9(1) of Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 for Chordhara Block].

M-N-K lines pass along the part eastern, northern and western boundary of Damodar river in village Chordhara and meet at starting point 'K'.

[No. 43019/33/84-CA]

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1986

शुद्धि पत्र

का.आ. 2660.--भारत के राजपत्र, तारीख 22 फरवरी, 1986 के भाग II खण्ड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 664 से 665 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 661, तारीख 4 फरवरी, 1986 में :--

पृष्ठ 664 पर--अधिसूचना में :--

(1) "पुवक्षण" के स्थान पर "पूर्वेक्षण" पढ़िए।
(2) "नागपुर 140004" के स्थान पर "नागपुर-440001" पढ़िए।

अनुसूची में--

(3) क्रमांक 1 में तहसील स्तम्भ के नीचे "आइनगढ़" के स्थान पर "आनगढ़" पढ़िए।
(4) क्रम सं. 4 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "पिनोरा" के स्थान पर "पिनौरा" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो वहां "पिनौरा" पढ़िए।
(5) क्र.सं. 5 में टिप्पण स्तम्भ के नीचे "सम्पूर्ण" के स्थान पर "सम्पूर्ण" पढ़िए।
(6) क्र.सं. 9 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "आमादोगरी" के स्थान पर "आमाडोंगरी" पढ़िए और जहां कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त किया हो वहां "आमाडोंगरी" पढ़िए।
(7) क्रम सं. 10 में साधारण संख्या स्तम्भ के नीचे "39" के स्थान पर "391" पढ़िए।

सीमा वर्णन में--

रेखा "ख-ग" में "कोहक" के स्थान पर "कोहका" पढ़िए।

[सं. 43015/27/85-सी ए]

New Delhi, the 10th July, 1986

CORRIGENDA

S.O. 2660.—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 661, dated the 4th February, 1986 published in the Gazette of India, Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 22nd February, 1986, at page 665 :—

Under the heading 'Boundary description',—

(1) in line 11, for "Dogdowa" read "Dagdowa";
(2) in line 15, for "through" read "through".

[No. 43015|27|85-CA]

का.आ. 2661.--भारत के राजपत्र, तारीख 19 अप्रैल, 1986 के भाग II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में पृष्ठ क्रमांक 1753 से 1755 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ.सं. 1562, तारीख 11 अप्रैल, 1986 में--

पृष्ठ 1754 पर--

(1) बेलटिकरी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट सं० में "365 से 372 (भाग)" के स्थान पर "365 से 372" और "529 से 531" के स्थान पर "528 से 531" पढ़ें।

[सं. 43015/28/85-सी ए]

S.O. 2661.—In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 1562, dated the 11th April, 1986, published at pages 1755 to 1757 of the Gazette of India, Part-II-Section 3-Sub-section (ii), dated the 19th April, 1986,—

AT PAGE : 1756 :—

In plot numbers acquired in village Dipka for "446" read "644";

AT PAGE : 1757 :—

In Boundary Description in line N-A for plot number "563" read "653".

[No. 43015|28|85-CA]

का० आ० 2662.--भारत के राजपत्र तारीख 15 फरवरी, 1986 के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 607 से 608 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 578, तारीख 29 जनवरी, 1986 में:--

पृष्ठ 607 पर-- अधिसूचना में :

(1) "राजस्व अनुभाग" के स्थान पर "राजस्व अधिकारी" पढ़िए

अधिसूची में :

(2) "करकाती ब्लाक" के स्थान पर "करकटी ब्लाक" पढ़िए।
(3) क्रम सं. 1 में क्षेत्र हेक्टर के स्तम्भ के नीचे "142.06" के स्थान पर "142.260" पढ़िए।
(4) क्रम सं. 8 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "बरसला" के स्थान पर "बरतरा" पढ़िए।
(5) क्रम सं. 9 में टिप्पणियां स्तम्भ के नीचे "भाग" के स्थान पर "सम्पूर्ण" पढ़िए।

पृष्ठ 608 पर सीमा वर्णन में :

(6) रेखा क-ख में "सरकरी" के स्थान पर "करकटी" पढ़िए।

[सं. 43015/30/85-सीए]

S.O. 2662.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 578, dated the 29th January, 1986, published at pages 608 to 609 of the Gazette of India, Part-II, Section 3-Sub-section (ii), dated the 15th February, 1986 at page 609, in the Schedule—

(i) for column heading "Sl.", read "Sl. No.";
(ii) against Sl. No. 12 under the main heading "District", for "South Shahdol Division, read "South Shahdol Division".

[No. 43015|30|85-CA]

का. आ. 2663.--भारत के राजपत्र तारीख 8 फरवरी, 1986 के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 530 से 531 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 491 तारीख 30 जनवरी, 1986 में :--

पृष्ठ 530 पर—अनुसूची "क" में :—

(1) क्रम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "जुगदी" के स्थान पर "जुगाडी" पढ़िए और तहसील स्तम्भ के नीचे "वानी" के स्थान पर "वणी" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "जुगाडी" और "वणी" पढ़िए ।

(2) क्रम संख्या 3 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "मुनगोली" के स्थान पर "मुंगोली" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "मुंगोली" पढ़िए ।

(3) क्रम संख्या 6 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "टाकली" के स्थान पर "टाकली" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "टाकली" पढ़िए ।

(4) क्रम संख्या 7 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "चिखाली" के स्थान पर "चिखली" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "चिखली" पढ़िए ।

(5) क्रम संख्या 8 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "परमडोह" के स्थान पर "परमडोह" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "परमडोह" पढ़िए ।

सीमा वर्णन ब्लाक-1 में :—

(6) रेखा "क-ख" में मनगंगा "पनगंगा" के स्थान पर "पेनगंगा" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "पेनगंगा पढ़िए ।

(7) रेखा "ख-ग" में "वनगंगा" के स्थान पर "पेनगंगा" पढ़िए।

(8) रेखा "ग-घ" में "चिखाली और कानखा" के स्थान पर "चिखली और चानखा" पढ़िए और "सिवानी और एनाक" के स्थान पर "सिवानी और एनाड" पढ़िए ।

(9) रेखा "च-क" में "बिन्द" के स्थान पर "बिन्दु" पढ़िए ।

अनुसूची "ख" में :—

(1) "आर. लकिल" के स्थान पर "राजस्व निरीक्षक मंडल" पढ़िए ।

(2) क्रम संख्या 1 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "संगोधा" के स्थान पर "सांगोडा" पढ़िए और "चंदूर" के स्थान पर "चान्दूर" पढ़िए और "राजरा" के स्थान पर "राजुरा" पढ़िए ।

पृष्ठ संख्या 531 पर :—

(3) क्रम संख्या 3 में 5 स्तम्भ के नीचे "राजपुरा" के स्थान पर "राजुरा" पढ़िए ।

(4) क्रम संख्या 4 में ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे "गदेगांव" के स्थान पर "गाडेगांव" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया हो उस जगह "गोडेगांव" पढ़िए ।

(5) क्रम संख्या 7 में 4 स्तम्भ के नीचे "शेराज" के स्थान पर "शेरज" पढ़िए ।

सीमा वर्णन ब्लाक-II में :—

(6) रेखा "क-ख" में "गडेगांव और खेरगाव व ग्राम गडेगांव और कावटगांव" का के स्थान पर "गाडेगांव और खैरगांव और कावटगांव की" पढ़िए ।

[सं. 19/47/83-सी.एल./मो.ए.]
समय सिंह, अवर सचिव

S.O. 2663.—In the notification of the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal, No. S.O. 497, dated the 30th January, 1986, published at pages 531 to 533 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th February, 1986, at page 532, under the heading "the Boundary Description Block-1.

(i) C-D, in line 2, for "Paramdok", read "Paramdoh";

(ii) D-E, in line 2, for "Siawni", read "Siwani" and in line 4, for "Kolagaon", read "Kolkaon";

(iii) E-E, in line 2, for "Villages", read "Village".

[No. 19|47|83-CL|CA]
SAMAY SINGH, Under Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का. आ. 2664.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्रालय की 10 जून, 1985 की अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित नैगमिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को, जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्तसारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में, जो कि उनकी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हों, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
1 उप निदेशक (सम्पदा एवं भवन) प्रशासन निदेशालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून-248003	उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाय इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।
2. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मक्करपुरा रोड़; बड़ौदा-390009	गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।
3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक अहमदाबाद परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अहमदाबाद-380005	गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।
4. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक (अंकलेश्वर परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अंकलेश्वर-393010	गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।

1	2
5. उप निदेशक, मेहसाना परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मेहसाना, गुजरात राज्य	गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
6. संयुक्त निदेशक, कैम्बे परियोजना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कैम्बे।	गुजरात राज्य के खेरा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
7. उप निदेशक, त्रिपुरा परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अगरतला-799001	त्रिपुरा राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
8. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पूर्वी क्षेत्र नजीरा।	असम राज्य में शिवसागर जोरहट जिले में शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, सरापत्थर, बोरहोला लकवा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में में आते हों।
9. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कच्छर परियोजना, सिल्चर	असम राज्य के कच्छर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
10. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासनिक) "कैलाश" कस्तूरबा, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।	दिल्ली/नई दिल्ली के संघशासित क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा या उसकी ओर से उनकी या पट्टे पर ली अथवा मांग की गई निजी सम्पदा, जो अन्य किसी सम्पदा अधिकारियों के नियंत्रण में न हो।

[फाइल सं. ओ-11023/1/85-ओ.एन.जी /डी-III]

सी. बी. भावे, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O. 2664.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the Notification dated the 10th June, 1985 of the erestwhile Ministry of Petroleum, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column 1 of the Table below, being Officers of the corporate authority, equivalent in rank to a gazetted Officer of Government to be Estate Officers for the purposes of the Said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, in respect of the premises specified in column 2 of the said Table :—

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Deputy Director (Estate and Housing) Directorate of Administration, Oil & Natural Gas Commission Dehradun-248003	Premises belongong to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District Dehradun Uttar Pradesh except such of them as are under the administrative control of the other Estate Officers.
2. Deputy Director (Personnel & Administration) Regional Office, Western Region, Oil & Natural Gas Commission, Makarpura Road Baroda-390009.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or o n behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District of Baroda Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
3. Deputy Director (Personnel Administration). Ahmedabad Project, Oil & Natural Gas Commission Ahmedabad-380005.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District of Ahmedabad, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
4. Deputy Director (Personnel Administration) Ankleshwar Project, Oil & Natural Gas Commission Ankleshwar-393010.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Baroach, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
5. Deputy Director, Mehsana Project, Oil & Natural Gas Commission Mehsana Gujarat State.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Mehsana Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
6. Joint Director, Cambay Project, Oil & Natural Gas Commission, Cambay.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Khara, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.

7. Deputy Director Tripura Project Oil & Natural Gas Commission Agartala-799001.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the State of Tripura except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
8. Deputy Director (Personnel & Administration) Oil & Natural Gas Commission Eastern Region, Nazira.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in Sibsagar Golaghat Jorhat, Sarupathar, Borhalla Lakwa in the district of Sibsagar Jorhat in Assam State, other than those under the administrative control of other Estate Officers.
9. Deputy Director (Personnel & Administration) Oil & Natural Gas Commission, Cachar Project, Silchar.	Premises belonging to, or take on lease or requisitioned by or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in district Cachar in Assam State, other than those under the administrative Control of other Estate Officers.
10. Deputy Director (Personnel & Administration) "Kailash" 6th Floor, 26, K.G. Marg, New Delhi.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in Union Territory of Delhi/ New Delhi, except such of them as are under control of the other Estate Officers.

[No. O-11023/1/85-ONG/D.III]

C. B. BHAVE Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का. आ. 2665.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवागाम जी. जी. एस-I से जी. जी. एस-III तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए तद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जी. जी. एस.-I से जी. जी. एस III तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला:—खेडा तालुका—मातर

गांव	सर्वे नंबर	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
नवागाम	747	0	02	00
	748/1	0	03	40
	749	0	03	50
	751/1	0	01	00
	738	0	06	35
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	706	0	03	25
	615	0	01	00
	621/2	0	02	05
	620	0	03	00
	619/2	0	00	45
	618/1	0	02	05
	617/3	0	03	10
	632/6	0	00	50
	632/4	0	01	25
	609/2	0	01	35
	646/2	0	02	00
	464/3	0	01	75
	470/2	0	03	25
	470/1	0	04	25
	493	0	02	20
	492	0	02	15
	491/1	0	02	15
	482/2	0	00	25
	490	0	02	70
	489	0	04	00
	482/3	0	01	00

[सं. O-12016/106/86-ओ एन जी. डी.- 4]

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2665.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Nawagam G. Gs. I to G G.S. III in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390003.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM GGS I TO GGS III

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Nawagam	747	0	02	00
	748/1	0	03	40
	749	0	03	50
	751/1	0	01	00
	738	0	06	35
	Cart track	0	01	00
	706	0	03	25
	615	0	01	00
	621/2	0	02	05
	620	0	03	00
	619/2	0	00	45
	618/1	0	02	05
	617/3	0	03	10
	632/6	0	00	50
	632/4	0	01	25
	609/2	0	01	35
	646/2	0	02	00
	464/3	0	01	75
	470/2	0	03	25
	470/1	0	04	25
	493	0	02	20
	492	0	02	15
	491/1	0	02	15
	482/2	0	00	25
	490	0	02	70
	489	0	04	00
	482/3	0	01	00

[No. O-12016/106/86-ONGD-4]

का. आ. 2666.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में नवागाम सी०टी० एफ से जी. जी. एस-I तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

555 GI/86—4

अनुसूची

नवागाम सी. टी. एफ. से जी. जी. एस-I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला:— खेड़ा तालुका:—मातर

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
नवागाम	887	0	03	75
	868	0	05	15
	869	0	02	35
	870	0	01	50
	871	0	03	00
	872	0	04	30
	879	0	04	25
	880	0	04	92
	954	0	02	75
	955	0	02	50
	956	0	01	25
	957/2	0	00	37
	964	0	00	50
	962	0	02	00
	973	0	04	35
	974	0	03	25
	976/ए	0	02	60
	987/1/ए	0	02	40
	989	0	02	40
	992/2	0	01	85
	992/1	0	01	00
	996	0	01	80
	998/2	0	01	00
	998/1	0	01	00
	998/3	0	01	00
	998/4	0	01	00
	999/2	0	01	85
	1000	0	03	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	155	0	03	50
	154	0	02	00
	157	0	02	00
	162/3	0	03	00
	859/1	0	01	75
	862	0	01	60
	858/2	0	01	60
	859/2	0	01	75

[सं. 0—12016/105/86—ओ एन जी डी-4]

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 2666.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Nawagam C.T.F. to G.G.S. I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390003).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM CTF TO GGS I

State : Gujarat District : Kheda Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
1	2	3	4	5
Nawagam	887	0	03	75
	868	0	05	15
	869	0	02	35
	870	0	01	50
	871	0	03	00
	872	0	04	30
	879	0	04	25
	880	0	04	92
	954	0	02	75
	955	0	02	50
	956	0	01	25
	957/2	0	00	37
	964	0	00	50
	962	0	02	00
	973	0	04	35
	974	0	03	25
	975/A	0	02	60
	987/1/A	0	02	40
	989	0	02	40
	992/2	0	01	85
	992/1	0	01	00
	996	0	01	80
	998/2	0	01	00
	998/1	0	01	00
	998/3	0	01	00
	998/4	0	01	00
	999/2	0	01	85
	1000	0	03	00
	Cart track	0	00	25
	155	0	03	50
	154	0	02	00
	157	0	02	00
	162/3	0	03	00
	859/1	0	01	75
	862	0	01	60
	858/2	0	01	60
	859/2	0	01	75

[No. O-12016/105/86-ONG. D. 4.]
P. K RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का.आ. 2667.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 806 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	क्योलारी	253	0-35	
				112	0-03	
				229	0-02	

[सं. O-14016/288/84-जीपी]

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2667.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 806 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Kyolari	253	0 35	
				112	0 03	
				229	0 02	

[No. O-14016/288/84-GP]

का.आ. 2668.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 808 तारीख 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	रैपुरा	31	0—12	

[सं. O-14016/308/84/जीपी]

S.O. 2668.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 808 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Raipura	31	0 12	

[No. O-14016/308/84-GP]

का.आ. 2669.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 805 तारीख 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के अर्योजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	गोरा राठौर	245	0—09	

[सं. O- 14016/187/8-4जी.पी.]

S.O. 2669.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 805 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Gora Rathaur	245	0 09	

[No. O-14016-187/84G.P.]

का. आ. 2670.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 129 तारीख 13-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय ससरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	देवगांव	504	0–01	

[सं. O.14016/315/84जी-पी.]

S.O. 2670.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 129 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Deogaon	504	0 01	

[No. O-14016/315/84-G.P.]

का. आ. 2671.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1296 तारीख 13-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	निजामपुर	145	0–10	
				146	0–06	

[सं. O-14016/188/84–जी.पी.]

S.O. 2671.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1296 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notificaction for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Nizam-pur	145	0 10	
				146	0 06	

[No. O-14016/188/84-G.P.]

का. आ. 2672 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. स. 804 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्र फल विवरण
जालौन	जालौन	जालौन	तातार-पुर	117	0–02

[सं. O–14016/183/84–जी.पी]

S.O. 2672.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 804 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submited report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Tatar-pur	117	0 02	

[No. O-14016/183/84-G.P.]

का. आ. 2673.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1289 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	चिरगांव	276	0 01	
			खुर्द	299	0 08	
				319	0 02	

[सं. -O14016/3/84-जीपी]

S.O. 2673.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1289 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Chirgaon	276	0 01	
			Khurd	299	0 08	
				319	0 02	

[No. O-14016/3/84-GJ]

का.आ. 2674.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1291 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बेलमा	129	0 02	
				653	0 02	
				797	0 01	
				871	0 01	

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2674.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1291 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notificationhereby for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Belma	129	0 02	
				653	0 02	
				797	0 01	
				871	0 01	

[No. O-14016/3/84-G.P.]

का.आ. 2675.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 807 तारीख 19/2/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आलौन	कोंच	कोंच	अटा	258	0 01	

[सं. O-14016/306/84-जीपी]

S.O. 2675.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 807 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Ata	258	0 01	

[No. O-14016/306/84-G.P.]

का.आ. 2676.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1290 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बरौदा	175	0	01

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2676.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 1290 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Baroda	175	0	01

[No. O-14016/3/84-GP]

का.आ. 2677.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1288 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	पुलगहना	176	0 50	
				253	0 10	

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2677.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 2288 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Pulgahan	176 253	0 50 0 10	

[No. O-14016/3/84-G.P.]

का.आ. 2678.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ.सं. 1292 तारीख 13/3/86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	लड़ावरा	603	0 10	
				624	0 02	
				633	0 06	
				651	0 04	
				654	0 04	
				653	0 04	
				638	0 05	

[सं. O-14016/3/84-जी.पी.]

S.O. 2678.—Whereas byb notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 1292 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Ladawara	603	0 10	
				624	0 02	
				633	0 06	
				651	0 04	
				654	0 04	
				653	0 04	
				638	0 05	

[No. O-14016/3/84-G.P.]

का०आ० 2679:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं. 802 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है; [1]

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।]

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	मिहौना	395	0-04	

[सं० O-14016/175/84-जी पी]

S.O. 2679.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 802 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Acre in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Mihauna	395	0 04	

[No. O-14016/175/84-G.P.]

का०आ० 2680 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन,) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं 809 दिनांक 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी भाराओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैसपाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोच	कोंच	तितरा-परसराम	58	0—38	

[सं० O-14016/310/84-जीपी]

S.O. 2680.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 809 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Titra Parasram	58	0—38	

[No. O-14016/310/84-G.P.]

का०आ० 3681 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 794/दिनांक 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
जालौन	कोंच	कोंच	खेड़ा-बेरा		0-03	

[सं. O-14016/310/84-जीपी]

S.O. 2681.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 794 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area acers	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Khera Bera	3	0 03	

[No. O-14016/32/84-G.P.]

का०आ० 2682.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 800 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	इमलिया स्टेट	121	0-02	

[सं०-O-14016/68/84-जीपी]

S.O. 2682.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 800 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

G.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Imalia Estate	121	0 02	

[No. O-14016/68/84-G.P.]

का॰आ॰ 268 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का॰आ॰ सं॰ 803 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच॰बी॰जे॰ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं॰	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	खकशीस	709	0—01	
				892	0—01	
				925	0—02	
				239	0—01	
				920	0—12	

[सं॰ O—14016/177/84—जीपी]

S.O. 2683.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 803 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pragana	Village No.	Plot No.	Area in Acers	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Khak-sees	709	0-01	
				892	0-01	
				925	0-02	
				239	0-01	
				920	0-12	

[No. O-14016/177/84-G.P.]

का॰आ॰ 2684 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का॰आ॰ सं॰ 812 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच॰बी॰जे॰ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं॰	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	[illegible]	[illegible]	1—02	

[सं॰ O—14016/410/84—जीपी]

S.O. 2684.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 812 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acers	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Bagha-wali Divara	23	1—02	

[No. O-14016/410/84-G.P.]

का. आ. 2865.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 795 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	डगरवाहा	932	0-12	
				949	0-03	
				1148	0-10	
				1461	0-04	

[सं. O-14016/37/84-जी. पी.]

S.O. [illegible]—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 795 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Dangar wahi	932	0 12	
				949	0 03	
				1148	0 10	
				1461	0 04	

[No. O-14016/37/84-GP]

का. आ. 2686.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1297 तारीख 13-3-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और, आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	एकों	525	0.01	

[सं. O-14016/186/84-जी. पी.]

S.O. 2686.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1297 dated 13-3-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Akon	525	0.01	

[No. O-14016/186/84-GP]

का. आ. 2687.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 798 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	रक्सा	123	0—20	
				150	0—22	
				155	0—11	
				684	0—29	
				124	0—02	
				379	0—00	
				522	0—62	

[सं. O-14016/66/84—जी पी]

S.O. 2687.—Whereas byy notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 798 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Raksha	123	0 02	
				150	0 22	
				155	0 11	
				684	0 29	
				124	0 02	
				379	0 02	
				572	0 62	

[No. O-14016/66/84-GP]

का. आ. 2688.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 819 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

—अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच बी जे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	पुनावली			
			कलां	2566	0–04	
				2617	0–02	
				2618	0–50	
				2510	0–07	
				2598	0–11	

[सं. O–14016/96/84-जी पी]

S.O. 2688.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 819 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Puna-wali Kala	2566	0 04	
				2617	0 02	
				2618	0 50	
				2510	0 07	
				2598	0 11	

[No. O-14016/96/84-GP]

का. आ. 2689.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 799 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	484	0–19	

[सं. O-14016/67/84-जी पी]

S.O. 2689.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 799 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Rajapur	484	0 19	

[No. O-14016/67/84-GP]

का. आ. 2690.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 793 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	सिरसा	238	0–02	
				327	0–20	

[सं. O–14016/5/84-जी पी]

S.O. 2690.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 793 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And further, whereas the Central Government has, after Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Sirsa	238	0 02	
				327	0 20	

[No. O-14016/5/84-GP]

का. आ. 2691.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम

मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 813 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या चक सं०	गाटा संख्या प्लाट सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	
जालौन	जालौन	जालौन	चाकी	594	1182 1169	0.59	

[सं. O-14016/432/84-जी० पी]०

S.O. 2691.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 813 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pip Line Project

Dis-trict	Tehsil	Pargana	Village	Plot No. Chak No.	Plot No.	Area in Hectare	Remark
1	2	3	4	5	6	7	
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Chaki	594	1182 1169	0.59	

[No. O-14016/432/84-GP]

का. आ. 2692.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 810 तारीख 19-2-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय-गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	रौमई	मुस्तकिल 754	0—08	

[सं. O-14016/313/84-जी० पी०]

S.O. 2692.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 810 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

H B J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Rampur Mustkil	764	0.08	

[No. O-14016/313/84-GP]

का. आ. 2693.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 797 तारीख 19-2-86 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि., में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	ऐरा	316	0-03	

[सं. O—14016/3/84-जी पी]

S.O. 2693.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 797 dated 19-2-86 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Supplementry Case (Schedule)

H B J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Aira	316	0 02	

[No. O-14016/3/84-GP]

का. आ. 2694.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उभराट से हजीरा तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजीरा प्रोजेक्ट, प्रहर, सुभाषनगर सोसायटी, घोडदोडरोड सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उभराट से हजीरा तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोर्यासी

गांव	ब्लॉक न.	हेक्टेयर	आर	सेंटीयर
भाटपोर	333	0	68	80

[सं. 12016/116/83-प्रो. जीपी]
राकेश कक्कर, उप सचिव

S.O. 2694.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from UBHARAT to HAZIRA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipeline (acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar" 60, Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heared in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pip line from Ubharat to Hazira

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi

Villag	Block No.	Hactar	Ar	Centiar
1	2	3	4	5
Bhatpore	333	0	68	80

[No. 12016/116/83-Prod./GP]
RAKESH KACKER, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का० आ० 2695.—वास्तुकला अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के खंड 3 और 5 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के खंड 3 उपखंड (3) की धारा (क) के अंतर्गत भारतीय वास्तुकला संस्थान द्वारा वास्तुकला परिषद् में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके सदस्यों में से चुने गए निम्नलिखित पांच वास्तुकारों के नाम इस सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है :—

नाम

1. श्री माधव गणेश देवभक्त,
मार्फत मैसर्स सेन एंड पेमास्टर
प्रोस्पैक्ट चैम्बर्स एनेक्सी,
तीसरी मंजिल
डा०डी०एन० रोड फोर्ट,
बम्बई-400001
2. श्री यतीश श्रीनिवास किनी
मैसर्स एस०एम० किनी एंड कम्पनी
134, नागिनदास मास्टर रोड फोर्ट,
बम्बई-400023
3. मैसर्स श्री दत्ता शान्ता राम मलिक
एस. के. मलिक एंड कंपनी,
क्रिसेंट चैम्बर्स तामरीन्ड लेन,
फोर्ट, बम्बई-400023
4. श्री अरुण विनायक ओगले,
सप्रे बंगलें, 15, हनुमान रोड,
दत्ता मंदिर के पास, विले पार्ले (पू.)
बम्बई-400057
5. श्री नटवरलाल अमृतलाल बड़ेका,
फेयरी मेनर, छठी मंजिल, 13 गलवे,
स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400001

तथापि, केन्द्रीय सरकार आगे यह भी बताती है कि उक्त अधिनियम के खंड 6 उपखंड (1) के अंतर्गत सदस्यों का कार्यकाल 24 जनवरी, 1986 से 23 जनवरी, 1989 तक तीन वर्षों की अवधि अथवा उनके उत्तराधिकारी चुने जाने तक, जो भी बाद में हो, के लिए होगा।

[संख्या एफ 17-16/82-डी-13/टी.-3 खंड-2]
डा. डी.सी. विश्वास, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O. 2695.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and 5 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government hereby notifies in the Offical Gazette the names of the following five architects elected from among its members by the Indian Institute of Architects to the Council of Architecture to represent the Institute under clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the said Act, namely :—

1. Shri Mahdav Ganesh Deobhakta,
C/o M/s. Sane and Paymaster,
Prospect Chambers Annexe,
3rd Floor, Dr. D. N. Road, Fort,
Bombay-400001.

2. Shri Yatish Shrinivas Kini,
M/s. S. M. Kini and Co.,
134, Nagindas Master Road, Fort,
Bombay-400023.

3. Shri Datta Shantaram Malik,
M/s. S. K. Malik and Co.,
Crescent Chambers, Tamarind Lane, Fort,
Bombay-400023.

4. Shri Arun Vinayak Ogale,
Sapre Bungalow, 15, Hanuman Road,
Near Datta Mandir, Vile Parle (E),
Bombay-400057.

5. Shri Natwarlal Amratlal Badheka,
Fairy Manor, 6th Floor,
13, Gunbow Street, Fort,
Bombay-400001.

The Central Government hereby further specifies that the members shall hold office under sub-section (1) of section 6 of the said Act for a term of three years commencing with effect from the 24th January, 1986 and upto 23rd January, 1989 or until their successors have been duly elected, whichever is later.

[No. F. 17-16/82-T. 13/7. 3 (Vol. II)]
DR. D. C. BISWAS, Jt. Education Advisor (Tech.)

परिवहन मंत्रालय

(रेल विभाग)

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1986

का०आ० 2696—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में परिवहन मंत्रालय, रेल विभाग (रेलवे बोर्ड), दक्षिण-पूर्व रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक बिलासपुर के कार्यालय को, जहां के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[संख्या हिंदी-86/रा. भा. I/12/3]

ए. एन. वांचू, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 11th July, 1986

S.O. 2696.—In pursuance of Sub-Rule (2) & (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Transport, Department of Railways (Railway Board) hereby notify the Office of the Divisional Rail Manager, Bilaspur of South Eastern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. Hindi-86/QL-I/12/3]
A. N. WANCHOO, Secy. Railway Board
and Ex-Officio Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1986

का.आ. 2697.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th July, 1986

S.O. 2697.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 1 of 1984

PARTIES : Employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers : Shri A. D. Singh, Dy. C. P. M. (Admn.), BCCL/Koyla Bhavan.

For the Workmen : Shri Brahmdeo Singh Yadav, the concerned workman.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 2nd July, 1986

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012 (235)/83-D. III, A, dated 17th/19th December, 1983, passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject-matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the action of the management of Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad in not regularising at Hindi Stenographers from November, 1980, Shri Umesh Kumar Singh, Bhatta Mazdoor and Shri Bhanmadeo Singh Yadav, Miner, Govindpur Colliery is justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The Memorandum of Settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Sec. 15 of the I. D. Act.

I. N. SINGH, Presiding Officer
[No L-20012/(235)/83-D. III (A)]

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT BETWEEN THE MANAGEMENT OF BOCL & WORKMAN NAMELY SRI BRAHMDEO SINGH YADAV, ADMN. DEPTT., KOYLA BHAVAN REPRESENTED BY BCC STAFF COORDINATION

For Management : Shri A. D. Singh Dy. CPM (Admn.) BCCL/Koyla Bhavan.

Workman : Shri Brahmdeo Singh Yadav.

An Industrial dispute was raised before the ALC(C), Dhanbad with regard to the regularisation of Shri Brahmdeo Singh Yadav as Jr. Steno (Hindi). The matter having failed was referred to Central Government Tribunal No. I, Dhanbad for adjudication where the same was numbered as ref.

No. 1|84 The terms of reference was —

"Whether the action of the management of BCCL, Dhanbad in not regularising as Hindi Stenographer from November, 1980, Sri Umesh Kr. Singh, Bhatta Mazdoor & Shri Brahmdeo Singh Yadav, Miner, Govindpur Colliery is justified ? If not, to what relief are these workmen entitled ?"

While the aforesaid reference case was pending for adjudication the workman approached for its amicably settlement. The matter was discussed on several occasions and ultimately it was agreed to settle the dispute amicably on the following terms :

TERMS OF SETTLEMENT :

1. That out of the two employees namely S/Shri Umesh Kumar Singh, Bhatta Mazdoor has since been died therefore, the question of his regularisation in any cadre doesn't arise.
2. That it has agreed that Sri Brahmdeo Singh Yadav earlier posted in Govindpur Colliery as Miner and now working in Admn. Deptt. at Koyla Bhavan will be regularised as Typist in the scale of Grade-II i.e. Rs. 678-30-918-35-1198/- immediately after Signing of this settlement without and difference of wages.
3. That the concerned workman will not claim any dues or arrears whatsoever, prior to the date of the present settlement.
4. That the party agreed to jointly file copy of the settlement before the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad for passing the award in terms of the settlement.
5. The settlement shall be registered under Rule 58(iv) of I.D. (Central) Rule, 1947.

Brahmdeo Singh Yadav,
14-6-1986
Workman

Sd|- Illegible
Management representative

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का.आ. 2698.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, गोविन्दपुर क्षेत्र नं. III, भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O. 2698.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Limited, in Govindpur Area No. III and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 74 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Limited in Govindpur Area No. III and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workman—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, Dated the 30th June, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012 (56)/85-D.III(A), dated the 29th May, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for regularisation of S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishra in clerical Special Grade in the Govindpur Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited is justified. If so, to what relief are these workmen entitled and from what date ?"

The case of the concerned workmen is that both the concerned workmen S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishra were Grade-I clerks working in the Finance department of Govindpur Area of M/s. B.C.C.L. Three special grade Clerks of Finance department/Accounts department retired and in their place the two concerned workmen were working as Special Grade Clerk. S/Shri R. L. Jain and K. S. Gorai special grade clerks had retired from service with effect from June, 1983 and November, 1983 respecively. Since their retirement the concerned workmen worked as special grade Clerks continuously and have put in more than 240 days attendance in each calendar year. The concerned workmen represented before the management for their regularisation as special grade Clerk and accordingly the Area Finance Manager initiated a notesheet dated 29-4-84 for their regularisation. The Personnel Manager, however, forwarded the notesheet with a recommendation for payment of difference of wages to the concerned workmen for working in higher post and it was accepted by the General Manager. The action of the management in not regularising the concerned workmen in the post of Special Grade Clerk was illegal, arbitrary and against the principles of natural justice and also against the policy decision of the management. A number of workmen have been regularised in the higher post by the management of BCCL if they had worked in the higher post for 240 days and more. S/Shri R. P. Paraser and A. K. Singh were regularised as Special Grade Clerks in the year 1983 although they were junior to many clerks. In the year 1979 the position of S/Shri R. P. Paraser and A. K. Singh and the concerned workman B. N. Jha in the seniority list was 27 and 191 and 105 respectively. Shri A. L. Parmer was also regularised in a Special Grade vide office order dated 22-1-81 although he was in Sl. No. 31 of the Seniority list. The promotional policy and job description will show that the concerned workman were performing the job of Special Grade Clerk. It is not true that Grade-I Clerks having a special merit are only promoted to special grade and they are promoted to continue in Grade-I job only with high efficiency. The promotional policy of the management, on the other hand, will show that the job description of Clerk Grade-I and Special Grade Clerks are different. As the concerned workmen have been working as a special grade clerk since 1983 against the permanent vacancy and they are senior in their cadre of Finance discipline, they are entitled to be regularised in Special Grade. The union of the workmen raised an industrial dispute before ALC(C), Dhanbad for conciliation. The management filed its comments before the consilation officer to the effect that the concerned workmen were not working as a Special Grade Clerk. The conciliation proceeding ended in failure and thereafter the present reference was sent for adjudication. On the above plea it has been submitted that the reference be made in favour of the workmen.

The case of the mangement is that the two concerned workmen are Grade-I Clerks working in the Finance department and that they have not yet been promoted to Special Grade Clerks as per rule of the company. Promotion is managements function and it is done according to the procedure laid down in the promotion policy. A Departmental Promotion Committee constituted to consider the case of all eligible candidates for their promotion and on the recommendation of the names of the candidates in order of merit for promotion by the D.P.C. their promotion is effected. The management has authorised the General Manager of different areas to make a stop gap arrangement and carry on the work of higher post by getting arangement whenever vacancies occurs in the higher post. The said higher post is generally to be filled up by promotion only. There is also practice of regularisation of workmen under which in a special circumstances a workman acting in higher post for a considerable period with exceptional merit, seniority and honesty may be regularised in that post provided there will be no other senior claimant to such post and it is not going to cause several dispute on behalf of others. This power given to the General Manager have to be sparingly used and cannot be invoked in all case to promote junior persons by way of regularisation on the basis of notesheets depriving claim of the senior workmen from their chances of promotion. Grade-I clerks are supposed to be competent enough to perform all types of duties concerning the departmental. In normal course Grade-I clerk is the higher clerical Grade. Grade-I clerk having a special merit are promoted to a special grade and they are promoted to continue the jobs of Grade-I with high efficiency. The concerned workmen being in Grade-I are performing Grade-I jobs only. They are junior to several workmen of Grade-I clerks working in Finance department performing similar types of jobs. The concerned workman are in no way more competent or meritorious to other clerks of the Finance department. The concerned workmen, therefore, cannot be promoted to special grade superseding the claim of their senior Grade-I clerks working in the same office and performing similar types of jobs. When any clerk of Grade-I is promoted to a special Grade he would be able to command respect of other clerks of Grade-I and should be able to exercise control over the clerks junior to him, and to supervise their duties. As the concerned workmen are junior to many Grade-I clerk who are much more competent than the concerned wrokmen, it will be different for the concerned workman to exercise control over their seniors. The concerned workmen have not worked as a Special Grade Clerk against permanent vacancy and that they have not put 240 days of attendance in a calendar year in the capacity of Special Grade Clerk. S/Shri R. L. Jain and K. S. Gorai have retired from their service and they were Special Grade Clerks at the time of their retirement. Prior to their promotion they were in Grade-I and were performing the same and similar types of jobs. Their promotion from clerical Grade-I to Special Grade did not change the contents of work but increased the efficiency and they exercise the power, control and supervision over their juniors. The Area Finance Manager wrongly recommended on the basis misrepresentation of facts by the concerned workmen as well as due to lack of his understanding about the fixation of grades and promotion for up-gradation of the concerned workmen. The management did not accept his recommendation. The order for payment of difference of wages to the concerned workman was incorrect and was sanctioned on wrong notings of the Area Finance Manager. A workman acting in higher post can claim for his promotion for that post by way of regularisation on the basis of officiating in that post unless it is established that there is no other candidates to claim for the post. The claims of the workmen is unreasonable illegal and without any basis and as such it cannot be allowed.

The schedule of reference refers to the case of regularisation of S/Shri B. N. Jha and B. D. Mishra. Shri B. D. Mishra did not appear and depose in the case. No evidence was adduced on behalf of B. D. Mishra. It was submitted by Shri D. Mukherjee representing the workmen that Shri B. D. Mishra was allotted some other job of Grade-I and he is not working in Special Grade and as such his case is not being pressed. It is further submitted by Shri D. Mukherjee that he would only proceed with the case of Shri B. N. Jha.

The point for determination in this case is whether Shri B. N. Jha can be regularised in Clerical Special Grade in Govindpur area of M/s. B.C.C. Ltd.

The workmen have examined three witnesses and the management have also examined three witnesses in proof of their respective case. The documents of the workmen have been marked Ext. W-1 to W-5 and the documents of the management have been marked Ext. M-1 to M-6.

Some facts are admitted. The concerned workman Shri B. N. Jha was working in Clerical Grade-I from 1980. S/Shri R. L. Jain, K. S. Gorai Special Grade Clerk retired from service with effect from June, 1983 and November, 1983 respectively and no fresh appointment was made in their place. The case of the workman is that the concerned workman was working as a Special Grade Clerk after the retirement of R. L. Jain and K. S. Gorai since June, 1983 and are continuing to work as Special Grade Clerk completing more than 240 days of atendance each year. The management on the other hand, contend that the concerned workman did not work as a special Grade Clerk and was working in Clerical Grade-1. WW-1 Nawal Kishore is working as an Accountant in Clerical Grade-I in the Finance department in Govindpur area office of M/s. B.C.C. Ltd. He has stated that in 1983 Shri R. L. Jain and K. S. Gorai, Special Grade Clerk retired and after their retirement there was no posting of Special Clerical Grade. He has stated that the concerned workman Shri B. N. Jha used to supervise the work of 4 to 5 Grade-I Clerks working in the Finance department. In the cross-examination he has stated that the concerned workman used to give him the journal vouchers which he used to enter in the ledger book WW-2 Bhuwal Singh Yadav is also working as an Accounts Assistant. He has stated that the concerned workman works in the Accounts Section and is full incharge of store accounting. He has stated that the concerned workman looks after the work of 4 of the clerks who work along with him. He has stated that Shri B. N. Jha was working as Specical Grade Clerk. He has also stated about the work being done by the concerned workmen as a Special Grade Clerk. WW-3 is the concerned workman Shri B. N. Jha himself. He has stated that from 1980 he was in Clerical Grade-1 and from 1933 he is working in Clerical Special Grade-I against the permanent vacancy in place of Shri R. L. Jain and K. S. Gorai who were working as special Grade Clerk after their retirement in 1983. He has stated that he was dealing with inter unit reconciliation with other area headquarters and Calcutta office since 1983. He has stated that there are four clerks attached with him whose work he checks. He also does the bank reconciliation, posting of bills, deals with purchase procedure and final accounting. He also makes entries of intricate case in the stores ledger. He supervises and controls the work of the 4 clerks attached with him. He is working continuously as a special grade Clerk since 1983 and had more than 240 days attendance in a year. He has further stated that BCCL has cadre scheme in which the description of clerical Grade-I and clerical special grade are given. The job description of Clerical Grade-I special grade are different. He has stated that he does the work which is given in the job description of clerical special grade in cadre scheme. He has further stated that the Area Finance Manager is his immediate superior who had initiated a note dated 22-2-84 which has been marked as Ext. M-1 in this case. The said note in Ext. M-1 was approved by the General Manager Shri S. B. Roy. He has stated that the Personnel Manager Shri R. Mohan had endorsed it to the Finance Manager for payment of difference of wages to him but the difference of wages as ordered vide Ext. M-2 was not paid to him. The photo copy of the notesheet was given to him by the Finance Maanger. MW-1 was working as Finance Officer and the concerned workman work under him from January, 1983 to December, 1985 and at that time the concerned workman was dealing with the stores and purchase accounts. There were staff working under MW-1 including the concerned workman and they had all been allotted different work and Shri B. N. Jha used to coordinate their work. This evidence shows that Shri B. N. Jha was doing some different work than the other staff and this work of coordination appear to be the job of superior order. He has also stated that the concerned workman used to see as to why the work of any member

staff was lagging behind and on the instructions from the Finance Officer the concerned workman used to complete the work which was lagging behind with any staff. In his cross-examination he has stated that he does not know the job of work of clerical special Grade and that he did not always consider the grade of his staff while allotting the duties to them. He came to learn from the concerned workman and other person that the General Manager had approved the recommendation of the Area Finance Officer regarding the regularisation of the concerned workman for the post of Special Grade Clerk. He had not himself seen the order of the General Manager. MW-2 Shri R. N. Prasad is attached to the Personnel Manager, Govindpur Area and deals with the file of the case. He has stated about the note of the Pesonnel Manager which was approved by the General Manager. He has stated that some clerks had objected and represented before the new Personnel Manager about the recommendation of regularisation of the concerned workman as Special Grade Clerk and thereafter the file went to the General Manager who kept the matter in abeyance till further order and thereafter no orde was passed on the said file MW-3 Shri S. C. Gour is working as a Personnel Manager. He has stated that the approval of the General Manager in Ext. M-1 was kept in abeyance for consideration of the representation of the staff and the union and the matter has not yet been decided. In his cross-examination MW-3 has stated that no individual worker had represented in writing about the so-called protest regarding the regulaisation of the concerned wokman in the special grade. He had not enquired whether the note sheet initiated by the Finance Manager was correct or false. He had to admit that if a workman of lower designation works in the higher designation, he gets the wages of the higher grade. He has also stated that the General Manager has the authority to pass order for regulatisation or payment of the difference of wages. Thus it is almost admitted that the case of the concerned workman was recommended for giving him clerical Special Grade.

Ext. W-1 is dated 22-2-84. WW-3 has stated that the notesheet Ext. M-1 dated 22-2-84 was initiated by the Area Finance Manager Shri S. N. Pathak bearing his signature. It will appear from this notesheet that there were representations from the concerned workman and Shri B. D. Mishra for their regularisation in Special Grade. Shri Pathak noted that the nature of work being performed by the concerned workman entitles him to the claim as he has been dealing with intricate jobs of double entry accounting and banking and other jobs involved special responsibilities. He has further recommended that in order to boost up morale of the staff the claims made for promotion to special grade may be allowed as has been done in a few case in 1983. Ext. M-2 is a note of the Area of the Area Finance Manager Govindpur Area dated 27-4-84. This note was made on receipt of reminder from the concerned workman for his placement in special Grade as per the nature of job being performed by him The Finance Manager has noted that the claim of the concerned staff is genuine and deserving consideration and he is perfoming the job of highly skill nature with trust and sense of responsibility independently i.e. Shri Jha is checking and scrutinising the bills and is fully conversant with purchase procedure, making proper entries in stores ledger and capable of dealing with intricate cases of stores final accounts and accounts reconciliation inter area and headquarters. He is also conversant with follow up action putting drafts or correspondence etc. He has stated that as 3 vacancies in the Finance Department has occurred due to the retirement of three special Grade Clerk a notesheet had previously been moved on 22-2-1984 (which is Ext. W-1). He recommended that the case of the concerned workman may be considered for proper placement in Special Grade. Below the said note is the note in which payment of difference of wages for working against a higher grade till some other suitable arrangement is done was recommended for G.M's approval and the G.M. approved the same on 7-5-84 Another photo copy of this notsheet has been filed by the management and the same is marked as Ext. M-1. The only difference in Ext. M-1 is there is a note written "This may be kept in abeyance for further orders." There is no such note in photo copy of the same notesheet Ext. W-2. It appears therefore that this note in red ink was noted sometime after the note Ext. W-2 was handed over by the Finance Manager to the concerned workman. In any case this noteshcet show that the concerned workman had performed the jobb of Special Grade Clerk and for this reason a recommendation was made atleast for the payment of diference of wages between the clerical Grade-I and Special Grade Clerk. Thus from the very document of the management it is clear that the concerned workman was working as a Special Grade Clerk. None of the management witnesses were able to clearly deny that the concerned workman was not performing the job of Special Grade Clerk. The workmen had filed a petition asking for the copy of promotion policy for ministerial cadres in BCCL but the management did not produce the same and did not give any explanation as to why the document which ought to be in their possession have not been produced in this case. It is said that the promotion policy gives the job description of the various clerical jobs including clerical Grade I and Special Grade Clerk. It has been submitted on behalf of the concerned workman that as the job being performed by the concerned workman was the job of Special Grade Clerk as has come in evidence, the management did not produce the said promotion policy as that would have gone against the case of the management. The submission made on behalf of the workmen appears to be correct and it was for this reason the management witness were evading to specify the job performance of Clerical Grade I or special Grade Clerk. From all the evidence which has been adduced in this case, there is no room for doubt that the concerned workman was performing job of Special Grade Clerk since the retirement of Shri R. L. Jain and S. K. Gorai in 1983.

It has been submitted on behalf of the workmen that in case of regularisation the seniority of a workman does not count. It is only to be seen whether the workman was working in the higher grade against the permanent post for a sufficiently long time and thereafter he may be regularised. It is further submitted that the case of the concerned workman is not for promotion but the case of his regulari- the job of Special Grade Clerk since 1983 when the perma- sation in the clerical special grade as he was performing nent incumbent on the post had retired. Some examples have been shown to establish that in the past workmen being junior have been regularised in the higher job being performed by him although there were senior clerks in the area. WW-1 has stated tht Shri A. K. Singh is junior to the concerned workman but was regularised in Special Clerical Grade and no D.P.C. was held for regularisation in special grade. WW-3 has stated that Shri A. K. Singh who is junior to him was regularised in clerical Special Grade in December, 1983 without holding any D.P.C. The seniority list Ext. M-2 has been filed by the management. It will appear from the said seniority list, Ext. M-2 that the seniority of the concerned workman Shri B. N. Jha is 104 whereas the seniority of Shri A. K. Singh was 190. MW-3 has stated that he does not know if Shri A. K. Singh who was promoted in December, 1983 was junior to the concerned workman Shri B. N. Jha. Of course the list Ext. M-2 itself shows that the concerned workman was senior to Shri A. K. Singh in the seniority list but Shri A. K. Singh was regularised in Special Grade Clerks whereas many seniors remained in their original grade. MW-3 has stated that he does not know if Shri A. K. Singh and R. P. Paraser were promoted to clerical special grade without holding any D.P.C. Thus he does not know about the fact whereas there is positive evidence adduced on behalf of the workmen that they were promoted in Clerical special grade without holding any D.P.C. The D.P.C. is constituted for consideration of promotion of the legible candidates and regularisation of a workman on the higher post is mater different from promotion and as such it appears that the case of regularisation of a workman is not considered by the D.P.C. The evidence in the case establishes that in the case of regularisation in the higher post seniority is not the criteria. The only criteria is whether he is doing job of higher grade for sufficiently longtime and because of the fact that the concerned workman has worked on the higher grade for a sufficiently longtime it was thought prudent that the said workman should be regularised in the higher post. It is for this reason that in the past also when case of regularisation was considered the seniority of the workman was ignored.

From the evidence discussed above it will appear that the concerned workman had performed the job of Special Grade Clerk since 1983 regularly and at one time his case was recommended for regularisation as a Special Grade Clerk, I hold that the case of the concerned workman Shri B. N. Jha is fit for regularisation as a Clerk Special Grade.

It will appear that the management did not actually pass any adverse order against the concerned workman as it appears from the note on Ext. M-1 that the approval in notesheet Ext. M-1 may be kept in abeyance till further order. Admittedly the management has not made any decision on the matter. As the case of the concerned workman was recommended vide Ext. M-2, for giving him clerical Grade-I and it was further recommended that he should atleast be paid the difference of wages of the higher grade, but as the matter was kept in abeyance since 23-5-84 and the matter has not yet been decided by the management, I think that the concerned workman should be regularised as Special Grade Clerk from 23-5-84.

In the result, I hold that the demand of Bihar Colliery Kamgar Union for regularisation of Shri B. N. Jha in Clerical Special Grade in Govindpur Area of M/s. B.C.C. Ltd. is justified and that Shri B. N. Jha should be regularised as Clerk Special Grade with effect from 23-5-84. Further, since Shri B. D. Mishra was allotted some other job and is not working in clerk Special Grade and has not given his evidence in support of his case, I do not pass any Award for his regularisation as Clerk Special Grade.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(56)/85-D.III(A)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का.आ. 2699.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की बसंतीमाता कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2699.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Basantimata Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 10 of 1986

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act. 1947

PARTIES : Employers in relation to the management of Basantimata Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powres conferred on them under Section 12(1)(d) of the I. D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(95)/85-D. III(A), dated. the 3rd January, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Basantimata Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P. O. Mugma, Distt. Dhanbad in denying employment to Kalipada Manjhi, dependent of late Sufal Manjhi who died during the tenure of his service, is justified. If not, to what relief is Kalipada Manjhi entitled and from which date ?"

The union representing the concerned workman appeared in the case and asked for adjournment for filling the W. S. Finally on 19-6-1986 Shri D. Mukherjee representing the union filed a petition praying to pass a 'No dispute' Award in this case on the ground that the issue in reference has been resolved and the dependant of Kalipada Manjhi has been provided employment and as such the union is not interested now to contest the case.

In view of the fact that the dispute has been resolved between the parties and the dependent of Kalipada Manjhi has been given employment, I pass a 'No dispute' Award in this case.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/95/85-D. III A]

का.आ. 2700.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि. की भौरा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2700.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhowra Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 42 of 1983

In the matter of industrial dispute under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the maangement of Bhowra Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri B. N. Sharma Joint General Secretary, Janata Mazdoor Sangh.

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act 1947 has referred the following dispute to this tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(434)| 82-D.III(A), dated the 5th May, 1983.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bhowra Colliery of Mesrs. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhowra, Distt. Dhanbad, in dismissing Sri B. K. Sharma, Store Issue Clerk from service with effect from 4th May, 1982 is justified ? If not to what relief is the said workman entitled ?"

In this case the parties filed their W. S. They were heared on the preliminary point whether the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper or not. On 15-5-86 it was held that the domestic enquiry held against the concerned workman was fair and proper. There after Shri B. N. Sharma, Joint General Secretary of Janta Mazdoor Sangh who had sponsored the industrial dispute filed a petition dated 30-6-86 praying that the case may be disposed off as the workman in the union are not now interested.

In the result as the union is not interested in proceeding with this reference a 'No dispute' award is passed in this case.

I. N. SINHA, Presiding Officer,

[No. L-20012(434)|82-D-III(A)]

का.आ. 2701.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि. की गजलीटांड कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-1986 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2701.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Gajlitand Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th July, 1986.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

Reference No. 33 of 1983

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Gazlitand Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the workmen: Shri S. Bose, Secretary, RCMS Union.

On behalf of the employers: Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY: Coal

Dated, Dhanbad, the 8th July, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(365)|82 DIII(A) dated the 30th March|11th April, 1983.

SCHEDULE

"Whether the dismissal from service of Shri N. K. Roy Bill Clerk of Gazlitand Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited, by the Agent, Gazlitand Colliery for the missing amount of Rs. 22,608 from the cash Box on 4|5-10-1981 from inside locked cash room, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri N. K. Roy was a permanent employee of Gazlitand Colliery of M|s. BCC Ltd. He was posted as Bonus Clerk but at the relevant time he was working as a Bill Clerk. He was entrusted with Rs. 93,200 on 4-10-81 for payment of salary|wages to the employees of the colliery for the month of September, 1981. He disbursed Rs. 68,598.00 of the employees and was required to return the balance undisbursed amount of Rs. 24,602 to the cashier towards the end of his duty. The concerned workman did not hand over the undisbursed amount to the cashier to be kept in the safe custory. He kept the wooden cash box in the cash room in the evening of 4-10-81 containing the undisbursed balance amount of Rs. 24,602. The other cash box were also kept in the said room. The cashier locked and sealed the said room and left his office. On the next day i.e. on 5-10-81 the cashier opened the room and along with him the concerned workman and other persons, who had kept the cash box in the said rooms entered to take their box. The concerned workman found the lock of his wooden box broken kept on the ground. Subsequently it was found that there was Rs. 1,914 left in the wooden box of the concerned workman but the rest of the amount of Rs. 22,688 was missing from the said box. The concerned workman informed the cashier about it and thereafter the cashier informed the higher authorities. A case was also lodged before the Police stating that there was theft of the said money from the cash box of the concerned workman. The Manager, Gajlitand Colliery vide his office memo dated 9-10-81 issued chargesheet to the concerned workman regarding the missing amount of money which was kept in the wooden box in the Colliery office cash room. The concerned workman submitted his explanation to the chargesheet. Thereafter the management held a departmental enquiry into the charges against the concerned workman for misappropriation of money of the management Rs. 22,688 on 4-10-81. The management examined witnesses in the departmental proceeding in presence of the concerned workman and gave him full opportunity to cross-examine them and to defend himself. After completing the enquiry the enquiry officer submitted his enquiry report holding the concerned workman guilty of the charges. Thereafter the Agent of the colliery issued a letter under his signature dated 12-1-82 without any authority dismissing him from service. The concerned workman approached the officers of the colliery at different levels and also submitted a petition in writing addressed to the Agent, Gajlitand colliery about his wrongful dismissal but no reply was received by the concerned workman. Thereafter the union of the workmen raised industrial dispute before the ALC(C) Dhanbad who took up the matter with the parties. He held the

conciliation proceeding which ended in failure and thereafter the present reference was made to this Tribunal for adjudication. The concerned workman had been made a scape-goat to save the skin of some other persons responsible for the missing amount from the management's colliery cash room. The charge against the concerned workman had not been established in the enquiry proceeding and the enquiry officer was made to submit a got up report against the concerned workman. It is submitted that the dismissal of the concerned workman by the Agent is not justified and that he should be reinstated with full back wages from the date of his dismissal till the date of his reinstatement as if he was never dismissed from service along with other benefits.

The cash of the management is that the concerned workman ought to have returned the balance undisbursed amount of Rs. 24,602 to the cashier towards the end of his duty but the concerned workman kept the amount with himself. The concerned workman had kept the wooden cash box on 4-10-81 without handing over the undisbursed amount to the cashier to be kept in the safe custody and left the office. On the next day (5-10-81) in the morning it was reported that the wooden box of the concerned workman contained only Rs. 1914.00 and the amount of Rs. 22,688.00 was missing. The police was immediately informed to investigate the facts and circumstances under which the loss of Rs. 22,688.00 occured. After a careful consideration of all the facts and circumstances of the present case it was observed that the concerned workman had committed the misconduct theft, fraud and dishonesty and was directly responsible for the loss of the amount. It was a cash of misappropriation of the amount and the concerned workman was trying to plant out a case of theft in a pre-planned manner to avoid the responsibility. The concerned workman was issued with a chargesheet dated 9-10-81 on the allegation of commission of the misconduct of theft to which he submitted his reply. Shri H. K. Choudhury Personnel Officer of Gajlitand Colliery was appointed to hold the enquiry into the chargesheet. The enquiry officer after serving the notice of enquiry conducted the enquiry on 25-11-81 to 27-11-81 in accordance with the principles of natural justice. The concerned workman along with his co-worker fully participated in the enquiry on all the dates. The witnesses of the management were examined in the presence of the chargesheet workman who was given full opportunity to cross-examine the management witnesses. The concerned workman gave his own statement before the Enquiry Officer. He was given full opportunity to produce his witness and documents in his defence. After examination of all the materials on record the enquiry officer held the concerned workman guilty of the misconduct alleged against him. The dismissal of the concerned workman was duly approved by the competent authority. The concerned workman was dismissed from his services by a letter dated 12-1-82 issued by the Agent of the colliery who is a competent authority to dismiss a workman under the Standing Orders. The action of the management is legal and bonafide and the concerned workman is not entitled to any relief.

Earlier on the prayer of the parties a preliminary issue was taken up for hearing in respect of the fact whether the enquiry was fair and proper and in accordance with the principles of natural justice By the order dated 20-3-86 this Tribunal held that the enquiry was fair and proper and that the principles of natural justice were adhered to.

Now the point for decision is whether the charge levelled against the concerned workman was established on the materials produced before the enquiry officer in the enquiry proceeding.

The management has produced papers regarding the enquiry proceeding and they have been marked Ext. M-1 to M-7. The concerned workman has produced judgement of the criminal case in respect of the said allegation which is marked Ext. W-1.

Ext. M-1 dated 9-10-81 is the chargesheet which shows that on 4-10-81 the concerned workmen was assigned to make monthly payment to the staff for the month of September, 1981 and for that purpose he withdrew a sum of Rs. 46,700.00 In the morning and Rs. 46,500.00 in the afternoon from the cashier and thus he had drawn a total sum of Rs. 93,200.00. It is further alleged that as per existing practice the concerned workman was supposed to make payment to the staff and deposit the unpaid amount with the cashier along with paysheets with signature and account showing payment having been made. It is further alleged that on 5-10-81 at 9.30 A.M. the concerned workman along with payment clerks went to the cashier's office to collect payment box for further payment on that day and that the concerned workman reported that the lock of his box was broken and that a sum of Rs. 22,688 was stolen by breaking open the lock of his payment box and that a sum of Rs. 1914.00 was found lying in the box. It was alleged that the theft was a manipulated one and that a sum of Rs. 22,688 had been misappropriated by the concerned workman on 4-10-81 since if at all there had been any theft in the cashier's room, the other payment box should have also been broken and money stolen. Ext. M-2 is the reply to the chargesheet submitted by the concerned workman denying the allegation of misappropriation by him. It is stated in the said reply that other cash box of other pay clerks were also found tampered with along with the cash box of the concerned workman of which the hook of lock was broken and the cash removed. It was not possible for the concerned workman to break the hook and lock of the cash box during the day hours. There is an open ventilator on the wall of the room of the cashier and probability of a thief entering inside the room of the cashier through the ventilator and committing the theft from the cash box of the concerned workman in collussion with the guard cannot be ruled out. Some foot prints and finger marks were found on the wall of the room of the cashier near the ventilator outside as well as inside the room.

Ext. M-4 is the enquiry proceeding and Ext. M-5 is the enquiry report. Ext. M-6 are the notes initiated by the Agent of Gajlitand Colliery containing the approval of the General Manager. Ext. M-7 is the dismissal letter issued to the concerned workman.

Let us now turn up to the Enquiry proceeding Ext. M-4 itself to see the evidence adduced on behalf of the management to prove the charge against the concerned workman. It is the admitted case of the parties that the concerned workman who was working as a Bill Clerk of Gajlitand Colliery was entrusted with Rs. 93,200.00 on 4-10-81 for payment of salary/wages to the employees of the colliery for the month of September, 1981. It is also admitted that the concerned workman disbursed Rs. 68,598.00 to the employees and there was a balance of undisbursed amount of Rs. 24,602 out of which Rs. 1914.00 was found in the cash box of the concerned workman in the morning of 5-10-81. It is also admitted that Rs. 22,688 was not found in the box of the concerned workman. The question therefore is whether this amount of Rs. 22,688 was misappropriated by the concerned workman.

The management examined before the Enquiry Officer Shri S. Mukherjee, Cashier of Gajlitand Colliery Shri D. D. Ghosh Head Clerk/Accountant Gajlitand Colliery Shri P. Choudhury, P. F. Clerk, Gajlitand Colliery, Kashinath Bhandari, Havildar, Sisir Kumar Dubey, Night Guard, M. G. Philip, Bill Clerk, Tal Bahadur Peon, Jagat Bahadur, Night Guard and Ramadhar Singh, Sub Inspector of Police, Katras None of these witnesses were eye witnesses to the theft or misappropriation of the amount from the cash box of the concerned workman. It was also not possible to get eye witness in a case of this nature and it is mostly the circumstances which would establish whether the allegation made against the concerned workman has been established or not. I will first take up the statement of the Sub-Inspector of Police Katras Shri Ramadhar Singh. The said Sub-Inspector had come to investigate into the information lodged before the police The Police had first registered a cash under Section 457 and 380 I.P.C. on the allegation made in the F.I.R. but subsequently the chargesheet was submitted under Section 409 I.P.C. against the concerned workman. He has stated that on perusal of the place of occurance he did not think the possibility of theft of money from the cash room through the ventilator on the ground that there was round the clock guard and that none of the guards stated before him about the appearance of any thief in connection with

the theft and therefore he concluded that the concerned workman had committed breach of trust in respect of money which had not been disbursed by him to the employees. It appears from his statement that he had found finger print and foot print at the place of occurrence which made allegations against the concerned workman doubtful. He has further given reasons as to why no thief would enter in the cash room through the ventilator because of its height and no support inside the room to reach the ventilator. In cross-examination he was asked about the height of the ventilator from the table inside the room which was about 8'-6". In his answer to another question he has stated that it was possible to reach ventilator after a jump from the table. He also stated that with the support of a chair and existence of projection in the wall, there was possibility of entering inside the room through the ventilator. He also stated that from the statement of the Peon he learnt that the cash room was not guarded by the guards from the eastern side.

It will appear from the evidence of S. Mukherjee, Cashier that Sudarshan Yadav informed him that hinges of his cash box which was kept in the cash room was also damaged. He has further stated that the employees were showing the foot prints inside the wall of the cash room. This witness had asked all the bill clerks to got out of the room and thereafter he went to inform his superior officer after locking the cash room. On his return and opening the cash room he had also seen the marks on the wall inside the cash room. Shri P. Choudhury had also gone along with the concerned workman and Shri M. G. Philips to take his payment box which was kept in the cash room. It will appear from his evidence that he had kept no money in his cash box. He has stated that he had seen foot print and finger prints on the wall inside the cash room. D. D. Ghosh had come in the cash room when S. Mukherjee had informed him about the breaking of the lock of the cash box of the concerned workman. He has stated that Shri S. Mukherjee had told him that the broken lock was shown to Shri S. Mukherjee which was lying on the ground. In his cross-examination he has stated that when he went inside the cash room he found the hinges and the lock of the cash box of the concerned workman broken and fallen on the ground. In answer to another question he has stated that a lin and thin person can enter inside the cash room through the ventilator in the wall of the cash room. It appears therefore that there was possibility of a thief entering inside the cash room through the ventilator. M. G. Philip, Bill Clerk had also gone along with the concerned workman inside the cash room when the cashier Shri S. Mukherjee opened the cash room at about 9.30 A.M. on 5-10-81. He had kept his cash box above the cash box of the concerned workman and he had also kept his pay sheet on his box which was not there and it was found inside the spittoon of the cacshier He has stated that the concerned workman told him at once that the lock of his payment box was broken and is fallen on the ground and thereafter the concerned workman reported the matter to the cashier. The payment box of witness M. G. Philip was in tact. He had also found foot prints and hand prints on the wall. He had found some nails fixed in the wall of the cash room. Thus from the evidence of above witness it is clear that a man could enter inside the cash room through the ventilator from outside and that he could also go out of the room through the ventilator. The fact that the witness found foot prints and hand prints on the wall inside the cash room also suggests the truth of the fact that the thief had entered inside the cash room and had escaped through the ventilator by scalting over the wall leaving marks of foot prints and hand prints. It will also appear that as soon as the concerned workman had entered inside the cash room when it was opened by the cashier, the concerned workman immediately told that the lock of his cash box was broken and was lying down on the ground. It will also appear that Shri Philip had kept his cash box upon the cash box of the concerned workman and Shri Philip also kept his pay sheets upon his own cash box. The said pay sheet was not found upon his box and the same was found in the spittoon of the cashier at some distance from the place where the boxes were kept. It also appears from the chargesheet Ext. M-1 itself that the hinges of cash box of Sudarshan Yadav was also damaged. There was no possibility of the concerned workman entering inside the cash box after he had kept his cash box in it as the said cash room had been locked and sealed by the cashier from outside and the said lock and seal was found intact in the morning when the cashier opened the room. There is no explanation by the management as to how the cash box of Sudarshan Yadav was also found damaged. There are the circumstances to show that some outside agency had entered inside the room may be through the ventilator and had taken out the money from the cash box. There is absolutely no evidence to show that the concerned workman had actually taken the money out of his own cash box. His house was also searched by the police but no amount was recovered from him.

Shri Kashinath Bhandari Havildar has stated in his cross-examination that when he went to the office at 7.30 A.M. on 5-10-81 he found the main gate open and Rajendra Singh orderly Peon who was deputed on duty at the gate was not on his duty. He had checked the lock of the office and had found the seal in tact. Sisir Kumar Dubey and Jagat Bhandari were Night Guards from 10.00 P.M. to 6 A.M. in the night between 4th and 5th of October, 1981. He has stated that nothing happened in the night. He had found the seal of the cash room intact when he had joined his duty. He has stated that they did not give round on all the 4 sides of the cash room. He used to watch by peeping through the gap of the door which was closed with a rope. It appears from his evidence that the watchman did not go on the eastern side in the round and that they only used to peep through the doors on the eastern side. Thus the possibility of thief coming from the eastern side of the cash room and committing theft from the eastern side through the ventilator cannot be ruled out.

I have discussed all the evidence on the record. The circumstances which have come in the evidence before the enquiry officer does not establish that the concerned workman had misappropriated the undisbursed amount lying with him on the contrary there is enough of evidence to show the possibility of theft inside the cash room through the ventilator of the cash room. In order to establish the charge on the basis of circumstances there must be evidence to cover all the loop holes leading to the only conclusion that it was the concerned workman who had committed the misappropriation of the money. In the present case as I have discussed above it appears that there is not much of circumstances to show that the concerned workman had misappropriated the amount. On the contrary there is material on the record to show that the amount had been stolen from the cash box of the concerned workman from the cash room and the thief had entered inside the cash room through the ventilator. As the watchman were not giving rounds on the eastern side of the cash room, the possibility of theft from eastern side appears all the more glaring. In the result, I hold that the management have not been able to establish the charge of misappropriation against the concerned workman and as such he deserves to be reinstated in his job.

In the result, I hold that the dismissal from service of the concerned workman Shri N. K. Roy, Bill Clerk of Gajlitand Colliery for the missing amount of Rs. 22,688.00 from the cash box on 4/5-10-81 from inside the locked cash room is not justified. The concerned workman is therefore reinstated in his service from the date of dismissal with all back wages and other consequential benefits which might be available to him.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(365)/82-D.III (A)]
A. V. S. SARMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का.आ. 2705.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप पैरा (1) के प्रतुपरण में, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 8 सितम्बर, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2918 तारीख 24 अगस्त, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6. श्री ए.बी. चौधरी,
श्रम सलाहकार,
इंडियन चेम्बर आफ कामर्स,
इंडियन एक्सचेंज
4, इंडिया एक्सचेंज प्लेस
कलकत्ता-700001"

(ii) क्रम सं. 11, 12, 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"11. श्री डी.पी. चक्रवर्ती, श्री अन्नपूर्णा कॉटन मिल्स एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड पी. 10, न्यू हावड़ा ब्रिज एप्रोच रोड, कलकत्ता-700001	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य जो सामान्यतः पश्चिमी बंगाल के निवासी हैं ।
12. श्री लाल बहादुर सिंह, संयुक्त महासचिव, आई.एन.टी.यू.सी. बंगाल, शाखा, 177/बी, आचार्य जगदीश बसु मार्ग, कलकत्ता-14	

[सं. वी 20012/1/83-पी एफII]

New Delhi, the 14th July, 1986

S.O.2702 :—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No.S.O.2918, dated the 24th August, 1934 published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated the 8th September, 1984, namely :—

In the said notification,—

i) for serial number 6 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

"6. Shri A.B. Chaudhuri,
Labour Advisor,
Indian Chamber of Commerce,
Indian Exchange,
4, India Exchange Place,
Calcutta—700001."

ii) for serial numbers 11, 12 and 13 and the entries thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted namely :—

"11 Shri D P. Chakravarti, Shree Annapurana Cotton Mills and Industries Limited, P-10, New Howrah Bridge Approach Road, Calcutta-700001.	Member of the Central Board of Trustees, Employees Provident Fund, ordinarily residents of West Bengal.
12. Shri Lal Bahadur Singh, Joint General Secretary, I.N.T.U.C., Bengal Branch, 177/B-Acharya Jagdish Bose Road, Calcutta-14.	

[No. V. 20012/1/83-PF-II]

का.आ. 2703:—मेसर्स इन्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड पोस्ट बाक्स नं. 509, पुर्नन्वापेट, विजयवाड़ा (ए.पी./5636) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुन्टूर को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने का व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुन्टूर के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस 35014(134)/86एस एस2]

S.O. 2703.—Whereas Messrs Indian Express (Madural) Private Limited, Post Box No. 509, Pqornandapet, Vijayawada Pin Code No. 560016 (AP/5635) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and maintained such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guntur and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/134/86 (SS-II)]

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का.आ. 2704.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जुलाई, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला संगरूर में संघेरा राजस्व ग्राम
हद बस्त नं. 49."

[संख्या एस-38013/23/86-एस एस-1]

New Delhi,, the 15th July, 1986

S.O. 2704.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th July, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Punjab, namely :—

**Revenue village of Sanghera,
Had Bast No. 49, in the
District Sangrur."**

[No. S-38013/23/86-SS I]

का.आ. 2705.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 16 जुलाई, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"कोट्टायम जिले के कोट्टायम तालुक में पेरुमबैकाड राजस्व ग्राम (कुमारानेलूर नामक क्षेत्र को छोड़कर) तथा कैपूजा राजस्वग्राम (अरपूकारा नामक क्षेत्र को छोड़कर) के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस-38013/24/86-एस एस-1]

S.O. 2705.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 16th July, 1986 as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely :—

"The areas within the revenue village of Perumbaikad (excluding the area known as Kumaranellure) and revenue village Kaipuzha (excluding the area known as Arpookara) in Kottayam taluk of Kottayam District."

[No. S-38013/24/86-SS. I]

का.आ. 2706.—मैसर्स नेशनल डेरी डिवेलपमेंट बोर्ड, आनन्द (गुजरात) (जी जे/6775) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के अधीन खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम

के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस 35014(193)86-एस एस-2]

S.O. 2706.—Whereas Messrs National Dairy Development Board, Anand, (Gujarat) (GJ/6775) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/193/86 (SS-II)]

का. आ. 2707.—मैसर्स ओ. एम. सी. कम्प्यूटर्ज लिमिटेड, पांचवीं मंजिल, चिनोय ट्रेड सेन्टर 116, पार्कलेन, सिकन्दराबाद, (ए. पी./12895) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस.-35014 (192) 86-एस. एस. -2]

S.O. 2707.—Whereas Messrs O.M.C. Computers Limited, 5th Floor, Chenoy Trade Centre, 116, Park Lane, Secundrabad (Andhra Pradesh) (AP/12895) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/192/86-PF-II (SS.II)]

का. आ. 2708.—मैसर्स दुर्गापुर स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, दुर्गापुर-713201, जिला बर्धमान, (वेस्ट बंगाल) (डब्ल्यू. बी./11732) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निपेक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड -क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे ; प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[फा. एस. 35014 (191) 86-एस. एस. -2]

S.O. 2708.—Whereas Messrs Durgapur State Transport Corporation Durgapur-713201, Distt. Burdwan, West Bengal (WB/4732) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount poyoble under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/191/86-PF-II (SS-II)]

का. आ. 2709.—मैसर्स दि नारथ एरकोट जिला को. ओ. स्पनिंग मिल्ज लिमिटेड, पोस्ट बोक्स नं. 1, आरीयूर तामिलनाडु (टी. एन./5505), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014(190)86-एस. एस.-2]

S.O. 2709.—Whereas Messrs The North Arvcot Distt. Co-operative Spinning Mills Limited, Post Box No. I, Ariyur-632055 (Tamil Nadu (TN/5505) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the natute of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional President Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection is the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu

and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/190/86 (SS-II)]

का.आ. 2710.—मैसर्स पंजाब अलकालिज एण्ड केमिकल लिमिटेड, एस. सी.ओ. 125-127, सेक्टर 17-बी, पोस्ट बाक्स नं. 152 चण्डीगढ़-160017 (पी.एन./9900) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014(189)86-एस.एस.-2]

S.O. 2710.—Whereas Messrs Punjab Alkalies and Chemicals Limited, S.C.O. 125-127, Sector 17-B, Post Box 152, Chandigarh-160017 (PN/9900) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/189/86 (SS-II)]

का.आ. 2711.—मैसर्स पंजाब बुलकाम्बरज लिमिटेड, धंटारी कलान, जी. टी. रोड, लुधियाना (पी.एन./5950) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप से दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस. 35014(195)86-एस.एस.2]

S.O. 2711.—Whereas Messrs Punjab Wool, combers Limited, Dhandari Kalan, G.T. Road, Ludhiana (PN/5950) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of returns, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/195/86 (SS-II)]

का.आ. 2712.—मैसर्स स्टील आथोरिटी आफ इंडिया, लिमिटेड, एलॉय स्टील्स, प्लांट, दुर्गापुर (बर्दवान) (डब्ल्यू.बी./12646) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014(194)86-एस.एस.2]

S.O. 2712.—Whereas Messrs Steel Authority of India Limited, Alloy Steels Plant, Durgapur-713208, District-Burdwan, West Bengal (WB/12646) (hereinafter refetred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adpoted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/194/86-(SS-II)]

का. आ. 2713.—मैसर्स मुकेरियन लिमिटेड, जी. टी. रोड, मुकेरियन (पंजाब) (पी. एन./9901) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस. 35014/188/86-एस. एस. 2]

S.O. 2713.—Whereas Messrs. Mukerian Paper Limited, G. T. Road, Mukerian, (Punjab) (PN|9901) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of Insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|188|86-(SS. II)]

का. आ. 2714.— मैसर्स राणे (मद्रास) लिमिटेड, 61, वैपाचरी रोड मद्रास-600032 (टी०एन० 1142) (जिसे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम

की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस.-35014/205/86-एस.एस.-2]

S.O. 2714.—Whereas Messrs. Rane (Madras Limited, 61, Valachery Road, Madras-600032 (TN/1142) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwth a translaton of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|205|86 (SS II)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1986

का. आ. 2715 :— मैसर्स अहमदाबाद प्यूपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., प्यूपल्स बैंक बिल्डिंग, करकं, पो, बो, नं-133 अहमदाबाद (जी जे./4656) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3230 तारीख 24-8-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 11-9-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 10-9-88 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/10/82-पी. एफ.-2/एस. एस-2]

New Delhi, the 21st July, 1986

S.O. 2715.—Whereas Messrs. The Ahmedabad People's Co-operative Bank Limited, People's Bank Building, Karank, P. B. No. 133, Ahmedabad (GJ|4656) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3230 dated the 24-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of three years with effect from 11-9-1985 upto and inclusive of the 10-9-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|10|82-PF. II(SS. II)]

का० आ० 2716.—मैसर्स यू. बी. एस. पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लि., 5, अंसारी रोड, पोस्ट बाक्स नं. 7015, नई दिल्ली (डी.एल/1061) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3945 तारीख 8-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 27-11-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 26-11-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, हुए सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सुचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का अंशदायी निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा, निगम बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(23)/82-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 2716.—Whereas Messr. U.B.S. Publishers Distributors Limited, 5, Ansari Road, Post Box No. 7015, New Delhi-110002 (DL|1061) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3945 dated the 8-11-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 27-11-1980 upto and inclusive of the 26-11-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/23/82-PF. II(SS. II)]

का.आ. 2717.—मैसर्स गाजरा गियर्स प्राइवेट लि., स्टेशन रोड, देवास, मध्य प्रदेश- 455001 (एम.पी./902) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2313 तारीख 6-5-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-5-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-5-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्यप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि, किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(30)/82/पी.एफ-2/एस.एस-2]

S.O. 2717.—Whereas Messrs. Gajra Gears Private Limited, Station Road, Dewas, Madhya Pradesh-455001 (MP/902) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2313 dated the 6-5-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-5-1985 upto and inclusive of the 20-5-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/30/82-PF. II(SS. II)]

का.आ. 2718.—मैसर्स गोयट्राज (इण्डिया) लि., तेज बिल्डिंग, बहादुरशाह जफर मार्ग, हई दिल्ली (डी.एल./743) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3035 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(52)/82/पी.एफ.-2/एस.एस-2]

S.O. 2718.—Whereas Messrs. Goetge (India) Limited, Tej Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002 (DL/743) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3035 dated the 17-8-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in

any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/52/82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 2719.—मैसर्स न्यू शोरोक मिल्स को-आपरेटिव कन्ज्यूमर्स सोसाइटी लि., नाडेज (जी. जे./4823) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमिय का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3039 तारीख 17-8-32 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/82/84-पी.एफ.-II/एस एस-2]

S.O. 2719.—Whereas Messrs New Shorock Mills Co-operative Consumers Society Limited, Nadiad (GJ/4823) (he einafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3039 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1981.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissoner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time,, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promnt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|84|82-PF. II(SS. II)]

का. आ. 2720.—मैसर्स साबरमाथा डिस्टिक कोआपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यसियन लि. (सायर डैरी) हिम्मतनगर (जे. जी./3558) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3044 तारीख 17-8-1982 के अनुसरण में और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 28-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन से सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक दायाद/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[स. एस-35014/97/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 2720.—Whereas M|s. Sabarkantha District Co-operative Mills Products Union Limited, (Sabar Dairy), Himatnagar (GJ|3558) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3044 dated the 17-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28-8-1985 upto and inclusive of the 27-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause(a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administraion of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioer, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|97|82-PF. II(SS.II)]

का.आ. 2721.—मैसर्स पांडीचेरी डिस्टिलरीज, गोऊवर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी (पी. सी./26) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3724 तारीख 11-10-82 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 30-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधी 'चारियों को उपलब्ध फायदों में सामूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारण वश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम होजाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा :

[सं. एस.-35014/123/82-पी. एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 2721.—Whereas Messrs. Pondicherry Distilleries, Goubert Avenue, Pondicherry (PC|26) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3724 dated the 11-10-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 30-10-1985 upto and inclusive of the 29-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the langauge or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had emplovee been covered under the said Scheme, the emplover shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/123/82-PF. II(SS.II)]

का. आ. 2722.—मैसर्स इन्डोलोवनबराऊ ब्रेवरीज लिमिटिड, 13/1 मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) (पी.एन. 4913) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क (1) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है, कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी प्रथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तनों से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, फरीदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा । तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता है वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देते समय पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/196/86-एस-एस.-2]

S.O. 2722.—Whereas Messrs. Indo Lowenoran Breweries Limited, 13/I Mathura Road, Faridabad (Haryana) (PN/4913) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Faridabad and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Reigonal Provident Fund Commissioner, Faridabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/196/86(SS.II)]

का.आ. 2723.—मैसर्स दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि., एफ ब्लाक, बम्बई लाईन बिल्डिंग, कनाट सर्कस नई दिल्ली (डी.एस. 3277) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 1952 का 19 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा

जिससे कि कर्मचारियों के लाभ सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(197)/86-एस-एस-2]

S.O. 2723.—Whereas Messrs. Delhi State Industrial Development Corporation Limited, N-Block, Bombay Life Building, Connaught Circus, New Delhi-110001 (DL|3277) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administraion of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the assurance benefits to the nominees or the legal heirs of Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in assurance benefits to the nominees or the legal heirs of payment of premium the responsibility for payment of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|197|86-(SS.II)]

का.आ. 2724.—मैसर्ज श्री प्रकाश टैक्सटाइल्स (गुजरात) प्रा लि., लक्ष्मी विजय होजरी मिल्ज कम्पाऊन्ड, नरोदा रोड, अहमदाबाद 380025 (जी./जे/2644) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा

गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014 (198)/86-एस.एस-2]

S.O. 2724.—Whereas Messrs. Shree Parkash Textiles (Gujarat) Private Limited, Laxmivijay Hosiery Mills Compound, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/2644) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administraion of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the langauge or the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall, immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/198/86 (S.S.II)]

का०आ० 2725.—मैसर्स मुंजाल मेंजीज, जी०टी०रोड, (हिरो नगर), लुधियाना-141003, (पी०एफ०/2539) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय अधिनियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस–35014(199) 86–एस.एस.-2]

S.O. 2725.—Whereas Messrs. Munjal Gases, G. T. Road (Hero Nagar), Ludhiana-141003 (PN/2530) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employee under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/199/86-(SS.II)]

का.आ. 2726.—मैसर्स पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि.एस.सी.ओ. नं. 315–16, सैक्टर–35–बी, चण्डीगढ़ (पी.एन./2827) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का सामाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा 3–क के खण्ड–क के अधीन समय–समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं। तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(200)/86-एस.एस-2]

S.O. 2726.—Whereas Messrs. Punjab Agro Industries Corporation Limited, SCO No. 315-16, Sector 35-B, Chandigarh (PN|2827) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Governmen. is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corpn. of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the permium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee

or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/200/86(SS II)]

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1986

का. आ. 2727.—मैसर्स रीटा मैकेनिकल वर्कस, 416, इण्डस्ट्रीयल एरिया-ए, लुधियाना (पंजाब) (पी एन./167) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (19 का 1952) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्ध के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चंडीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चंडीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014 (200)/86-एस. एस. -II]

New Delhi, the 21st July, 1986

S.O. 2727.—Whereas Messrs. Rita Mechanical, 416, Industrial Area-A, Ludhiana, (Punjab) (PN/167) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/201/86(SSII)]

का. आ. 2728—मैसर्स मोपेड इन्डिया लिमिटेड, रेनी गुनता रोड, नेटोपली, पोस्ट, तिरुपति-517506 (आन्ध्र प्रदेश) (ए पी/2824) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम फौरन दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे; प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(202)/86-एस एस-2]

S.O. 2728.—Whereas Messrs. Mopeds India Limited, Renigunta Road, Settipalli Post, Tirupati-517506 (Andhra Pradesh) (AP|2824) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is saitsfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features hereof, in the language of he maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|202|86(SS-II)]

का.आ. 2729.—मैसर्स करीम कैटररज, वसीरबाग, हैदराबाद 500029 (ए.पी./6320) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952) 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे; प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(203)/86-एस एस 2]

S.O. 2729.—Whereas Messrs. Cream Caterers, Bashisbagh, Hyderabad—500029 (AP|6320) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposits Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of

the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/203/86-SS.II]

का. आ. 2730.—मैसर्स फूड, प्लांट, बीकानेर, ए यूनिट आफ राजस्थान को. ओ., डेरी फैडरेशन लि., नियर गांधी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर (आर. जे./2904) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम के सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट, न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम का संदाय प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (204)/86-एस. एस-2]

S.O. 2730.—Whereas Messrs. Cattle Feed Plant, Bikaner, A unit of Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited, Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur (RJ|2904) (hereinafter referred to as the said establishment) have aplied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintainance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respeit of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees available under the said Group Insurance Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir| nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of which exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme of Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month fro mthe receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|204|86(SS.II)]

का. आ..2731—मैसर्स पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, जी. टी. रोड, ए. के. नगर, नैलौर, आन्ध्र प्रदेश (ए. पी./14126) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2 क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जायें, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में

उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(207)/86-एस एस-2]

S.O. 2731.—Whereas Messrs. Pinakini Gameena Bank, G.T. Road, A.K. Nagar, Nellor (Andhra Pradesh) (AP|14126) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-24014/207/86 (SS. II)]

का. आ. 2732.—मैसर्स श्री राम रेयान्स, आकाश दीप, बाराखम्भा रोड़, पोस्ट बोक्स नं. 445, नई दिल्ली-110001 (डी.एल/5817) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहें हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2950 तारीख 4-8-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 21-8-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 20-8-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्वअनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014(208)/86-एस एस-2]

S.O. 2732.—Whereas Messr. Shri Ram Rayons, Akash Deep, Barakhamba Road, Post Box No. 445, New Delhi-110001 (DL/5817) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2950 dated the 4-8-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule an-

nexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 21-8-1985 upto and inclusive of the 20-8-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits avaialable to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits avaialable under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. Within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of dafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any iase within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|208|86(SS. II)]

का० आ० 2733:—मैसर्स अभिनाथ [illegible]टाईल लिमिटिड गांव मोलापुर, डा० शाहबाना चण्डीगढ़ रोड, लुधियाना (पी० एन० / 7534) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का यह उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के

अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/206/86-एस०एस-II]

S.O. 2733.—Whereas Messrs Adhinath Textiles Limited, (PN/7534) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/206/86-(SS. II)]

का० आ० 2734.—मैसर्स देहली इलैक्ट्रिक स्पलाई अण्डरटेकिंग शक्ति सदन, नई देहली-1100002 (डी० एस०/138) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप

सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 4256 तारीख 26-11-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (257)/82/पी.एफ-2-एस.एस.-2]

S.O. 2734.—Whereas Messrs Delhi Electric Supply Undertakings, Rajghat Power House, Shakti Sadan, Delhi-110002 (DL/138) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4256 dated the 26th November, 1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18th December, 1985 upto and inclusive of the 17th December, 1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language or the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/257/82-PF. II (SS. II)]

का. आ. 2735.—मैसर्स जुआरी एग्रो कैमीकल्स लि., जय किसान भवन, जुआरी नगर, गोवा (एम. एच/9969) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 738 तारीख 18-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 29-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 28-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तरीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (292)/82-पी. एफ-2/एस. एस- 2]

S.O. 2735.—Whereas Messrs Zuari Agro Chemicals Limited, Jai Kissan Bhavan, Zuarinagar, Goa (MH/9969) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Goyenment of India in the Ministry of Labour, S.O. 738 dated the 18-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 29-1-1986 upto and inclusive of the 28-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishemtn exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the empolyee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the reponsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have ben covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/292/82-PF.II(SS.II)]

का. आ. 2736.—मैसर्स नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्किटिंग फैडेरशन आफ इन्डिया लि., सपना बिल्डिंग, 24 ईस्ट आफ कैलाश पी. बी. नं. 3580, नई दिल्ली (डी एल/1507) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं व ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 617 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में और इसके उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-6-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के उपबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दहली को ऐसी विवरणियां भजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा

निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्व दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014 (296)/82 पी.एफ. 2/एस. एस 2]

S.O. 2736.—Whereas Messrs National Agricultural Co-ope ative Marketing Federation of India Liimted, Sapan Building, 24 East of Kailash P.B. No. 3580, New Delhi (DL/1507) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without makingg any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corp ration of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 617 dated 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of the 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be les sthan the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the Interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/296/82-PF.II(SS.II)]

का.आ. 2737.—मैसर्स दी भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, कामधेनु सेनावति बापत मार्ग, पुणे-411016 और इसकी शाखाएं जो अधिनियम के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से नहीं आती है (एच/15684) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1620 तारीख 5-3-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 19-3-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 18-3-1089 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों से प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजकों द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कामचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014 (310)/82-पी. एफ. 2 एस.एस.-2]

S.O. 2737.—Whereas Messrs The Bhartiya Agro Industries Foundation, Sanapati Bapat Marg, Poona-411016 and its branches not covered under the Act independently (MH/ 15684) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Empolyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Lite Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable, to such employees' than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1620 dated the 5-3-83 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estabilshment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 19-3-1986 upto and inclusive of the 18-3-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilties for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintanance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an empolyee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the repsonsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/310/82-PF.II(SS.II)]

का.आ. 2738.—मैसर्स सालीम टैकसटाइल्स लि., सैज्यायपालियम, नरसिंहापुरम, पो. आ. आतूर, तालुक, जिला, सालीम-636108 (टी. एन./6517) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4278 तारीख, 26-11-1982 के अनुसरण में और और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 18-12-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 17-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(342)/82-पी.एफ.-2/एस.एस.2]

S.O. 2738.—Whereas Messrs Salem. Textiles Limtied Selliampalayam, Narasingapuram, P.O. Attur, Taluk, Salam District-636108 (TN/6517) (hereinafter referred to as the said estabilshment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4278 dated the 26-11-82 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 18-12-1985 upto and inclusive of the 17-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insuranie Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced to that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendments likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in anycase within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/342/82-PF.II(SS. II)]

का.आ. 2739.—मैसर्स वसन्त फाइन आर्ट लिथोवर्क्स, मनोहर कालोनी रोड, गोंडिया, जिला बान्द्रा (एम.एच/3549) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 616 तारीख 13-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-1-86 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-1-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(342)/82/पी.एफ.-2/एस.एस. 2]

ए.के. भट्टाचार्जी, अवर सचिव

S.O. 2739.—Whereas Mesars Vasant Fine Art Litho Works, Manohar Colony Road, Gondiya-441614, District Bandara (MH/3549) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of the India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible

under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 616 dated the 13-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-1-1986 upto and inclusive of the 21-1-1989.

SCHEDULE

1. The empolyer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and mtaintain such accounts and provide such facilties for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shal display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and whenamended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay neecssary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give areasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/362/82-PF.II(SS. II)]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का.आ. 2740.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, बीकानेर द्वारा 61 ग्रामीण पीस-रेटिड कर्मकारों की छटनी के लिये अनुमति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में, अनुबंध में निर्दिष्ट, औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9 जुलाई, 1986 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2740.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, relating to the request of M/s. Rajasthan State Mines and Minerals Ltd., Bikaner for permission to retrench 61 village piece-rated workers, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

ANNEXURE

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. C.I.T. 16|86.

M|s. Rajasthan State Mines and Minerals Limited, Bikaner;

VS

Their Workmen.

PRESENT

Shri R. S. Verma, R.H.J.S.

For the Workmen : Shri J. L. Shah.

For the Employer : Shri V. P. Agrawal.

Date of Order : 26-4-86.

ORDER

The Government of India, being the appropriate Government in the matter, has made this reference under Sub-section 6 of Section 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter called "The Act," vide its notification No. L-29024(1)|86-II(B) dated 28th Feb., 1986.

> "Whether the request of M|s. Rajasthan State Mines and Minerals Limited, for permission to retrench 61 village piece-rated workers, whose particulars are given in the annexure, is justified ? If so, to what relief are the workmen concerned entitled."

2. The reference was received in this Tribunal on 7-3-86 and was placed before me on 10-3-86. Since correspondence was pending between the Tribunal and the Ministry of Labour, Government of India, regarding issue of notification under section 8 of the Act, and no final reply had been received from the aforesaid Ministry, the matter was posted to 7-4-86 so as to enable the Tribunal to have a final reply from the aforesaid Ministry. However, since no final reply

whatever, was received from the aforesaid Ministry and time was running out, the Tribunal proceeded with the hearing of the reference. Shri J. L. Shah, appearing on behalf of the workmen filed his claim on 7-4-86. On being pointed out that the claim was to be filed by the employer, the parties agreed that the employer may file its claim and claim filed by Shri Shah may be treated as reply to the claim, in addition to such reply, as Shri Shah may choose to file after the claim has been filed by the employer. Accordingly, Shri V. P. Agrawal filed the claim on behalf of the employer on 9-4-86. Shri J. L. Shah filed reply on behalf of the workmen on 16-4-86.

3. In his claim petition, the employer has raised a number of objections to the legality and maintainability of the reference, as also regarding jurisdiction of this Tribunal to proceed with the reference. Both the parties wanted these objections to be tried as preliminary issues, hence on 16th April, 1986 itself, following preliminary issues were framed. Both the parties agreed before the Tribunal that these issues did not require any evidence. As such, these issues have been heard as preliminary issues :

(i) Whether the reference is without jurisdiction because appropriate Government|Specified authority has not passed an order under section 25-N of the Industrial Disputes Act ?

(ii) Whether the reference could have been made only to Central Industrial Tribunal and refrence to this Tribunal is abinitio void ?

(iii) Whether this Tribunal has no jurisdiction because no notifications have been issued under section 8 of the Industrial Disputes Act ?

(iv) Whether this Tribunal has no territorial Jurisdiction to hear the matter ?

(v) Whether the Tribunal has no jurisdiction to proceed with the matter since it did not enter into reference within 30 days of the date of order of reference ?

(vi) Whether this Tribunal is not the correct forum to decide competence of the reference and jurisdiction of the Tribunal.

(vii) Whether under the circumstances of the case, it is to be deemed that Government had refused to grant permission to the employer to retrench the workman ?"

4. I have heard Shri V. P. Agrawal for the employer and Shri J. L. Shah for the workmen at some length since the issues go to the very root of the matter. I have also perused the material available on record. I have given my earnest consideration to the arguments of rival sides.

5. Before I deal with the issues, I may be briefly narrate the undisputed facts of the case. M|s. Rajasthan State Mines and Minerals Limited is a State controlled company, duly registered under the Indian Companies Act with head-quarters at Bikaner. It has gypsum mines at Jamser in the district of Bikaner. It decided to retrench 61 workmen, working at the Jamser mines and submitted an application to the Central Government for permission to retrench such workers under section 25-N of the Act. This application was moved on 1st|2nd Jan., 1986. The Government of India also received representations against the said application. No specific order, granting or refusing the application appears to have been passed by the said Government. However, it chose to make a reference to this Tribunal, as stated above.

6. To appreciate the rival contentions, it would be useful to have a look at provisions of section 25-N of the Act. It reads as follows :

"25-N. Conditions precedent to retrenchment of workman :—

(1) No workman employed in any industrial establishment to which this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until:—

(a) the workman has been given three months' notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, for the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice; and

(b) the prior permision of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has been obtained on an application made in this behalf.

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended retrenchment and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workman concerned in the prescribed manner.

(3) Where an application for permission under sub-section (1) has been made, the appropriate Government or the specified authority, after making such enquiry as it thinks fit and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, the workmen concerned and the persons interested in such retrenchment, may, having regard to the genuineness and adquacy of the reasons stated by the employer the interests of the workmen and all other relevant factors, by order and for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such permission and a copy of such order shall be communicated to the employer and the workmen.

(4) Where an application for permission has been made under sub-section (1) and the appropriate Government or the specified authority does not communicate the order granting or refusing to grant permission to the employer within a period of 60 days from the date on which such application is made, the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of sixty days.

(5) An order of the appropriate Government or the specified authority granting or refusing to grant permission shall, subject to the provisions of sub-section (6) be final and binding on all the parties concerned and shall remain in force for one year from the date of such order.

(6) The appropriate Government or the specified authority may, either on its own motion or on the application made by the employer or any workman, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) or refer the matter or, as the case may be, cause it to be referred, to a Tribunal for adjudication.

Provided that where a reference has been made to a Tribunal under this sub-section, it shall pass an award within a period of 30 days from the date of such reference.

(7) Where no application for permission under sub-section (1) is made or where the permission for any retrenchment has been refused, such retrenchment shall be deemed to be illegal from the date on which the notice of retrenchment was given to the workman and the workman shall be entitled to all the benefits under any law for the time being in force as if not notice had been given to him.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions this section, the appropriate Government may, if it is satisfied that owing to such exceptional circumstances as accident in the establishment or death of the employer or the like, it is necessary so to do, by order, direct that the provisions of sub-section (1) shall not apply in relation to such establishment for such period as may be specified in the order.

(9) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section (3) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under sub-section (4) every workman who is employed in that establishment immediately before the date of application for permission under this section shall be entitled to received at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to 15 days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months."

7. The first contention of Shri V. P. Agrawal is that the reference is without jurisdiction since the appropriate government has not passed a reasoned and speaking order as envisaged by section 25-N (3) of the Act. This contention is the subject matter of perliminary issue No. 1. Shri Agrawal contends that passing of an order under sub-section (3) of section 25-N of the Act, is a condition precedent to the making of the reference. Shri J. L. Shah, on the other hand contends that passing of an order under sub-section (3) is not and cannot be a condition precedent for making a reference under section 25-N (6) of the Act. However, he agrees with Shri Agarwal that this reference was bad in as much copies of application of the employer were not served on individual workman as required by sub-section (2) of the above section. He contends that service of copy of the application on each individaul workman was mandatory and in absence of compliance with the said provision, there was no proper application before the Union Government. Without a valid application, the Union Government was not competent to make this reference.

8. Shri V. P. Agrawal states that he does not conceed but is not in a position to take the stand that copies of the application had been served on individual workmen.

9. A bare reading of the section shows that an application by the employer is the very foundation for action under this section. Provisions of sub-section (2) of the section are very categorical and clear and mandate that "a copy of such application shall also be served simultaneously on the workman concerned in the prescribed manner." There is a clear cut object behind this rule of law. Sub-section 3 of the section envisaged quasi-judicial|administrative enquiry before the appropriate Government and a workmen can adequately meet the application, only when he has been supplied with a copy of the same. I, therefore, agree with Shri Shah that service of the copy of the application on each workman is a sine qua non for the further action in the matter. In the present case, though some representations appear to have been made before the appropriate Government, it does not appear from the reference that copy of such application had been made available to each and every induvidual workman. I am, therefore, of the view that the appropriate Government did not acquire proper jurisdictional foundation to make a reference to this Tribunal and on this short ground, the reference is liable to be rejected.

10. However, I find it difficult to agree with Shri Agrawal that a reasoned order is a condition precedent to make a reference. Suffice it to say that in appropriate case, the appropriate Government may not pass any order at all what to say of a reasoned order and in that case, after expiry of period of 60 days, application of the employer shall be deemed to have been granted by virtue of sub-section (4) of the aforesaid section. I decide the issue accordingly.

11. ISSUE No. 2 and 3,

Shri V. P. Agarwal contends that the matter could have been referred only to a Tribunal constituted by the Central Government and not to a Tribunal constituted by the state Government. He contends that the reference does not indicate as to which Tribunal the matter was referred. If it is assumed that the reference was made to the Tribunal constituted by the Central Government, then Constitution of the Tribunal is invalid, since no notification has been issued under section 8 of the Act. Shri Shah contends that reference does not indicate that it was referred to a Tribunal constituted by the Central Government, hence it may be assumed that it was referred to the Tribunal constituted by the State Government and the reference is valid.

12. Here, I may state that this Tribunal has been constituted by the State Government. This Tribunal

has also been functioning as a Tribunal constituted by the Central Government but since no notification has been issued under section 8 of the Act, cases referred to the Tribunal by the Central Government are not, making any progress. As indicated at the outset, the correspondance made the Tribunal with the Labour Ministry, Government of India has not borne any fruit.

13. Shri Agrawal is right that the reference does not explicitly indicate to which Tribunal it has been made. It would have been better if the reference would have specifically said to which Tribunal the matter has been refrred, viz. to one constituted by the Government or to one constituted by the Central Government. However, all official acts are presumed to be done correctly, hence, I assume that the reference has been made to the Tribunal constituted by the State Government, because it is this Tribunal which has been validly constituted so far.

14. The contention of Shri Agrawal is that Central Government is the appropriate Government for purposes of this matter, as per definition of "appropriate Government" given in section 2(a) of the Act. Prior to amendment made by Act No. 46 of 1982, all references, whether under section 10, or section 25-N used to be made by the appropriate Government to corresponding Tribunal constituted by appropriate Government. So far as section 10 was concerned, the position was changed by the aforesaid amendment and a third proviso was inserted in section 10, so as to enable the Central Government to make a reference to a Tribunal constituted by the State Government. A similar amendment was not made in section 25-N and hence, it can be safely assumed that the Parliament did not envisage any change, so far as references to be made under this section were concerned. He submits that under section 10 of the Act, it is industrial dispute which is referred to a Tribunal but under section 25-N (6), an industrial dispute is not referred rather only an application of the employer is referred. This is a function to be performed under amended section 7A by a Tribunal constituted by the appropriate Government. Shri J. L. Shah contends that section 25-N refers only to 'a Tribunal' hence, the Central Government was competent to refer the matter even to a State Tribunal.

15. I have given my earnest consideration to the rival contentions and must say that contention of Shri Agrawal stands on a sound footing Section 7 (A) (1) of Act read as follows :

> "7-A. Tribunals-(1) The appropriate Government may by notification in the official Gazette, constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes relating to any matter, whether specified in the Second Schedule or Third Schedule (and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act)."

A bare reading of this section shows that the appropriate Government constitutes one or more Industrial Tribunals for adjudication of industrial disputes, as also for performing such other functions as may be assigned to them under the Act. It is a settled position that prior to the amendment mentinoed above the Central Government could refer the industrial dispute and ask perfomance of other functions, only by a Tribunal constituted by it. By the amendment under reference, a third proviso was added to section 10 and this proviso now enables the Central Government to refer an industrial dispute to a State Tribunal also. No similar amendment has been made in section 25-N (6) of the Act. Hence, it is obvious that so far as section 25-N (6) is concerned, no change was contemplated in the forum by the Parliament. This is true that section 25-N (6) refers to 'a Tribunal' but this reference has to be read in context of the provisions of section 7A of the Act. It may be stated that no industrial dispute has been referred under section 10 of the Act but only a matter has been referred by the appropriate Government, which falls within the purview of 'such other functions' of the Tribunal, as envisaged by section 7A of the Act and hence, the Central Government could have referred the matter only to a Tribunal constituted by it under section 7A of the Act. Reference, assuming it to be a State Tribunal is bad in law. The Central Tribunal has not been duly constituted by the issuing a notification u|s 8 of the Act and as such the reference is not entertainable. The issues are decided accordingly.

16. ISSUE NO. 4,

Assuming for the sake of arguments that the reference was to a State Tribunal and not to a Tribunal constituted by the appropriate Government, Shri Agarwal contends that this State Tribunal does not have jurisdiction over Division, where the Mines are situated. Shri Shah contends that the appropriate Government may refer the dispute to any Tribunal irrespective of territorial jurisdiction, Section 7A of the Act, as such does not expressly stipulate that an industrial Tribunal may be constituted for a particular area, 'but perhaps the very scheme of action 7A empowers the appropriate Government to constitute a Tribunal for any limited time or for a particular case or a number of cases or for a particular area.' (Please see O. P. Malhotra, The Law of Industrial Disputes, Fourth Edition, Page 544). If a Tribunal has been specifically constituted for a specific area, then it may be argued that it has no jurisdiction beyond its territorial limits. But in the present case, no notification has been brought to my notice, which confines the territorial limits of this Tribunal to any geographical area. Hence, this objection of Shri V. P. Agrawal deserves to be noticed only for the sake of rejection. Issue is decided accordingly.

17. ISSUE NO. 5 :

The contention of Shri Agrawal is that even if for the sake of arguments, it is assumed that this Tribunal had jurisdiction, the jurisdiction has come to an end by effluxe of time. He contends that proviso to section 25-N (6) mandates that the Tribunal shall pass an award within a period of 30 days from the date of reference. The reference was made on 28-2-86. Thirty days expired on 30-3-86. Hence, no award can be passed now. He submits that by virtue of section 25-N (5), a disability attaches to the employer and he may not make a fresh application for a period of one year Shri Shah contends that section 25-N(5) does not create any disability, whatsoever. The pro-

visions of proviso to section 25-N (6) are directory and not mandatory. The term of one month, looking to the volume of work in the various Tribunals is impracticable.

18. I have considered the rival contentions. To my mind provisions of section 25-N (5) do not create any disability and the order of the appropiate Government has been made specifically subject to the provisions of sub-section (6) when the order made by the Government is subject to provisions of sub-section (6), it is obvious that the operation of the order would comence from the date of final order made under sub-section (6). To my mind, the provision fixing the period in the proviso to sub-section (6) is only directory and not mandatory. I am supported in my view by the observations in O.P. Malhotra's. "The law of Industrial Disputes" Fourth Edition, Page 1425 when the learned author observors ;

> "The proviso prescribes the time limit of thirty days from the date of reference during which the Tribunal should pass its award. From the use of the word 'shall' it would appear that the requirement of the proviso that the award should be made within thirty days from the date of reference, is mandatory. Furtharmore, there is no power vested in the Tribunal to extend the period of adjudication. But can it be said that an award made beyond thirty days will be invalid and inoperative. From the scheme of the Section the answer should be in the negative. Though making of the award is mandatory, the requirement to make the award within thirty days appears marely to be directory."

Shri J. L. Shah has referred to certain rulings also but since I have accepted his contention, I need not refer to those rulings. Hence, I decide the issue accordingly.

19. ISSUE NO. 6.

This issue has not been pressed before me. I am of the view that this Tribunal can decide if the reference was valid or not. It can also determine if it has jurisdiction to hear the matter or not. Therefore, decide the issue accordingly.

20. ISSUE NO. 7 :

Shri Shah contends that the appropiate Government did not pass any order as envisaged by section 25-N (3) but has referred the matter. Hence, it should be presumed that the application of the employer has been rejected. Hence, the reference itself does not survive. I think that the argument is not sound. Rather, when the appropriate Government has not made any order under section 25-N (3), then by virtue of section 25-N (4), the permission applied for shall be deemed to have been granted on the expiration of sixty days from the date of making application by the employer under section 25-N(2). However, since in this case it has not been shown that copies of application, had been served on each individual workmen, it is not free from difficulty to spell out if the consequence mentioned in section 25-N(4) will flow from the act of not passing any order by the appropriate Government. I decide the issue accordingly.

21. In view of what I have said above, this reference is invalid and incompetent and fails. Let a copy of this order be sent to the appropriate Government for such action, and is deemed proper at that end.

R. S. VERMA, Judge

[No. L-29024|1|86-D. III (B)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1986

का.आ. 2741—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार च राजरप्पा प्रोजेक्ट मैसर्स सी सी लि. डाक राजरप्पा जि. हजारी बाग, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10/7/86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 15th July, 1986

S.O. 2741.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajrappa Project of Central Coalfields Limited, P.O. Rajrappa, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1986.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 173 of 1985

In the matter of industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Rajrappa Project of M|s. C. C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES

On behalf of the workmen.—Shri Lalit Burman, Vice President, United Coal Workers Union.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

State : BIHAR Industry : COAL

Dated, Dhanbad, the 30th June, 1986

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adiudication vide their Order No. L-24012(24)|85-D.IV(B), dated the 3rd December, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Rajrappa Project of C. C. Ltd., P.O. Rajrappa, Distt. Hazaribagh in terminating the services of Shri Lalan Tiwari, Driver is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Lalan Tiwari was appointed as a driver in Cat. V. vide letter dated 9|12-4-1983 in a permanent vacancy. As usual he was kept on probation for a period of 6 months for verification of his character and antecedents. Subsequently by an order dated 26-5-1983 he was posted in excavation section of Rajrappa Project with effect from 26-5-1983. There was never any complaint regarding his conduct and services during the period of his employment in the excavation section of Rajrappa Project. The management issued a chargesheet dated 11-9-1983 against the concerned workman making certain allegations and the workman was put under suspension with effect from 11-9-1983. The concerned workman submitted his explanation dated 13|16-9-1983 denying all the allegations made against him in the charge and pleaded not guilty of the alleged misconduct. The management by memo dated 2|4-10-1983 proposed to hold enquiry into the charges against the concerned workman and by further memo he was allowed to resume his duties with effect from 22-10-1983. The enquiry officer held the enquiry on 10-10-1983 at 10.00 A.M. The said enquiry was neither just nor proper. The concerned workman asked for the copies of the enquiry proceeding and the enquiry report from the management but the management refused to furnish the same to him. The management terminated the services of the concerned workman with effect from 9-11-1983 vide memo dated 9-11-1983 without giving any reason whatsoever. The concerned workman lodged a protest against the said action of the management. The case of the workman was taken up by the union before the ALC(C) Hazaribagh. The conciliation proceeding was started which ended in failure. Thereafter the dispute was referred to this Tribunal for adjudication.

The management had not asked for a report about the performance of the concerned workman in the first week of November, 1983. There was never any adverse report against the concerned workman and the alleged report was prepared just on the eve of the termination of the services of the concerned workman and after the conclusion of the disciplinary proceeding. The management adopted a circuitous and questionable method to get rid of the services of the concerned workman. The action of the management in terminating the services of the concerned workman is neither legal nor justified as it amounts to colourable exercise of the powers and victimisation in total violation of the provision of the Standing Orders. The action of the management is mala fide.

On the above plea it is submitted that the workman is entitled to get the relief of reinstatement with full back wages and other benefits with effect from 9-11-1983 as also the full wages for the period of suspension from 11-9-1983 to 21-10-1983.

The case of the management is that the reference is bad in law in as much no dispute was raised by the workmen directly with the management nor any demand was made by the workmen on the management at any time before raising the dispute before the ALC(C) Hazaribagh. The reference is barred by the express contract of service between the concerned workman and the management. The concerned workman had been issued with an appointment letter dated 9|12-4-1983 offering him appointment as a probation Cat. V subject to the terms and conditions specified therein. He joined the duty on 10-5-1983 after accepting the said terms and conditions. He was appointed only for a period of 6 months and was placed on probation during the period his retention in the service for a further period was to depend on the receipt of the report about his work during his period of probation. In the event of a report declaring him not fit for employment, his services on probation were liable to be terminated without assigning any reason during the probationery period. His retention for a further period was to depend on receipt of the report about his work during the period of probation. In the first week of November, 1983 a report about his performance was obtained. The report was called for which indicated that the concerned workman lacked devoation to his work and indulged in indecent behaviour and was also not amenable to discipline. It was also reported that he was undesirable workman. On consideration of the said report and considering the terms and conditions of his appointment it was decided by the management of Rajrappa area that the services of the concerned workman should be terminated. In the meantime an enquiry report relating to disciplinary case in which the concerned workman was found guilty was also placed before the General Managr|C.M.E. Rajarappa area and having regard to the enquiry report as a result of the domestic enquiry, the General Manager| CME decided that since the concerned workman is considered to be undesirable element he should not be continued in the services of the management. The fact that the concerned workman was on probation at that time was also taken into account while coming to the said decision. Accordingly the management issued an order on 9-11-1983 terminating the services of the concerned workman from the said date. It was alleged in the charge in respect of which domestic enquiry was held against the concerned workman that on 10 9 1983 the concerned workman was on duty in 3rd shift starting from 10.00 P.M. At about 10.15 P.M. on that day he went in Rajrappa Project canteen in drunken condition and broke the glass panes by hitting it with his fist. He was also shouting abusive, filthy language at that time in the canteen. He was prevented from further damaging the canteen materials by the employees present there at that time who took the concerned workman out of the canteen. As the concerned workman was completely drunk and was unable to perform his duties he was sent back by truck by the shift incharge at about 11.00 P.M. On receipt of the said report the concerned workman was issued with a chargesheet dated 11-9-1983 to which he submitted his explanation. The explanation was found to be unsatisfactory by the Project Officer|Agent of Rajarappa Project and he ordered a detailed enquiry into the charges framed against the concerned workman. Shri A. K. Das, S.O. S.O.M. (M.S) was appointed as enquiry officer. The enquiry officer held the enquiry in which

the concerned workman fully participated being associated by a co-worker during the enquiry. The management's witnesses were examined in their presence and the concerned workman was given full opportunity to cross examine the management's witnesses. The concerned workman was also given an opportunity to make statement and to produce his witness in defence. The enquiry was held in accordance with the principles of natural justice and all possible and reasonable opportunities were given to him to defend himself. The enquiry officer found the concerned workman guilty of the charges framed against him except the charge of being in a drunken state. The result of the domestic enquiry was also sufficient to administer that the concerned workman was not a fit person to be allowed further continuance in the services of the management beyond the initial period of 6 months for which he was employed on probation. On the above facts it is submitted on behalf of the management that their action in terminating the services of the concerned workman is legal and justified and that he had not right to continue in the employment of the management beyond 9-11-1983.

The only question to be determinated in this case is whether the termination of the services of the concerned workman was legal and justified with effect from 9-11-1983.

The management examined two witnesses and the workmen examined one witness in support of their respective cases. The documents produced on behalf of the management have been marked Ext. M-1 to M-15 and the documents of the workmen have been marked Ext. W-1 and W-2.

Admittedly the concerned workman was appointed as a driver in Cat. V on probation for a period of 6 months. Ext. M-1 dated 9|12-4-1983 is the appointment letter which sets out the terms and conditions of his appointment. It appears from Ext. M-1 that the appointment was purely on probation for a period of 6 months and subject to the satisfactory verification of character and antecedents. His probation may have to be extended till a report verification of his character and antecedents is received from the District Magistrate|Dy. Commissioner within the period of his probation. It is further stated that his retention in service for a further period was to dependent on receipt of the report about his work during his period of probation, and in the event of a report declaring him not fit for employment his services on probation was to be terminated without assigning any reason during the period of probation. The case of the management is that when the concerned workman was to complete his probationery period the Dy. P.M (R) asked for his performance report for his probationery period and thereafter Sr. Executive Engineer under whom the concerned workman was working submitted his report on 5-11-1983. Ext. M-10 is the note by which the Dy. P.M. had asked for a performance report of the concerned workman and thereafter the executive engineer Shri Om Prakash Kakroo submitted his report to the following effect. "He lacks devotion to work and indulges in indecent behaviour. He is not amenable to discipline also. It may be summed up that Shri Lalan Tiwary is an undesirable workman. Necessary action on the basis of the above may be taken." MW-1 is Shri Om Prakash Kakroo who has given this report about the concerned workman. The said report of Shri Kakroo was considered and in view of the performance report and the report reviewed by the Dy. C.M.E(F) and Personnel Officer (RP) it was confirmed that the work performance and behaviour of the concerned workman was not good. The report was submitted to the General Manager for necessary orders and the General Manager ordered that as the work|performance etc. of Shri Lallan Tiwari has not been found to be satisfactory during the probationery period, his services may be terminated on expiry of the probationery period. All these notes are contained in Ext. M-10 and it has been proved by MW-1. It will thus appear from Ext. M-10 and the evidence of MW-1 that the services of the concerned workman were terminated as his work performance and behaviour was not found satisfactory during the period of probation. M-7 is the memo dated 9-11-1983 by which the services of the concerned workman was terminated. Ext. M-7 shows that the concerned workman was purely on probation for a period of 6 months and as such his services were terminated with effect from 9-11-1983 and accordingly he ceased to be in the services of CCL with immediate effect. It has been submitted on behalf of the management that in accordance with the terms and conditions of his services as laid down in Ext. M-1 the services of the concerned workman was terminated as the report was obtained showing that he was not fit for employment. Admittedly the concerned workman was working under MW-1 Shri Kakroo and there is nothing in the evidence of MW-1 to show as to why he would make any false report against him.

The certified standing orders Ext. M-11 has been filed by the management which is applicable to all the workmen of CCL. In S.O. 3(c) probationer is defined as one who is provisionally employed to fill a vacancy in permanent post and has not completed 6 months in that post. The other part of the definition is not relevant for the purpose of our case. From the terms and conditions of services stated in Ext. M-1 it will appear that a probationer does not automatically attain permanent status on the expiry of his period of probationership. If a probationer is neither discharged nor confirmed he continues to serve as probationer until otherwise dealt with. It rests with the satisfaction of the employer whether a probationer had put in satisfactory service or not. Such satisfaction cannot be objectively decided and an employer is not bound to give any reason if he does not confirm a probationer on the expiry of the period of probationership. If an employer acts within his discretionary right it is difficult to ascertain mulafides against him. An employer need not given any reason for discharging a probationer. Even if certain reasons given by the employer does not appeal to the Tribunal, it cannot take away or detract the employer from such right. Thus as admittedly the order of termination of the services of the concerned workman was passed prior to the completion of the probationery period of 6 months. The employer was quite within its competence and authority to terminate the services on the ground that the performance of the probationer was not satisfactory.

Admittedly a chargesheet had been submitted against the concerned workman for misconduct and

the concerned workman had given his reply to the chargesheet. It will also appear from the evidence of MW-2 who was the enquiry officer that the concerned workman along with his co-worker had participated in the enquiry and that all the management's witnesses were examined in his presence and he was given an opportunity to cross-examine the management's witnesses. On perusal of the enquiry proceeding Ext. M-13 it appears that the concerned workman and his co-worker had cross-examined the management's witnesses and they had signed on each page of the enquiry proceeding indicating that they were present in the enquiry proceeding although. It will also appear from the enquiry proceeding that the concerned workman had given his statement and had also examined witnesses in his defence. On perusal of the evidence of the three witnesses examined on behalf of the management in the enquiry it appears from the evidence of MW-1 who was working as a canteen boy that the concerned workman had used abusive language and had broken glass panes and thrown other materials of the canteen. MW-1 has stated that the concerned workman himself had thrown glass and water and that the ground of the canteen was not slippery. The other two witnesses examined on behalf of the management did not fully support the management's case and the management witnesses No. 2 had almost turned hostile and gave his statement supporting the defence version. However, the fact that the concerned workman had broken glass panes etc. is established by the reply of the concerned workman in Ext. M-3. The concerned workman has stated in Ext. M-3 which is the reply to the chargesheet that "He had entered local canteen of project for getting some refreshment. He has toned to the counter with the ticket and he slipped before the counter and to save himself he had stretched his hand and with the body weight on his hand the glass panes on he counter was broken and he was injured in his hand and that when he tried to stand up some aluminium glass on the counter slipped down due to his body touch.". He has also stated in Ext. M-3 that he had abused the canteen employees after he got the inqury by fall. In his statement before the enquiry officer the concerned workman answered to question No. 10 that he had abused the canteen employees when he had got bleeding injuries. Although the evidence before the Enquiry Officer was meagre and was supported by the evidence of canteen by only nonetheless there was evidence to the effect that the concerned workman had broken the glass panes of the show case of the canteen and he had thrown some materials and that he had also abused the employees of the canteen. It cannot therefore be said that the finding of the enquiry officer was perverse and was not based on the evidence on the record.

It will appear from Ext. M-7 that the concerned workman was not dismissed on the basis of the finding of the Enquiry Officer but it appears that the enquiry was taken into consideration as a material to show that the conduct of the concerned workman was not satisfactory so as to confirm him after the period of probation. The concerned workman WW-1 himself has stated in his examination-in-chief that the management did not take any action on the basis of the chargesheet but terminated his services on the basis of Ext. M-7. Thus there is no room for doubt that the services of the concerned workman was terminated because of his unsatisfactory performance during the probationery period. As the management was within his authority to terminate the services of a probationer during the probationery period for unsatisfactory performance, I do not think it to be a fit case where the Tribunal can interfere with the said order of the management.

In the result, I hold that the action of the management of Rajarappa Project of Central Coalfields Ltd. in terminating the services of the concerned workman Shri Lallan Tiwary, Driver is legal and justified and consequently he is not entitled to any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer.

[No. L-24012(24)|85-D.IV(B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1986

का.आ. 2742.—औद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मिलिट्री डेरी फार्म के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 4/7/86 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th July, 1986

S.O. 2742.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Military Dairy Farm and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th July, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI

I. D. No. 28|86

In the matter of dispute between :

Shri Amar Singh c|o Shri Naresh Kumar, 1098 Bengalli Mohalla, Ambala Cantt.

Versus

Assistant Director, Military Dairy Farm, Ambala Cantt.

APPEARANCES :

Shri Charan Dass Kamra UDC—for the management.

None—for the workman.

AWARD

The Central Government, in the Ministry of Labour vide its notification No. L-13012(13)|84-B.II (B) dated 29 January, 1986 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of Military Farm, Ambala Cantt, in terminating

the services of Shri Amar Singh, a monthly rated Farm Labour working at Military Farm, Ambala Cantt, with effect from 3rd May, 1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled to and from what date ?"

Notice of the reference was sent to the parties. The workman had put in appearance on 7-5-86 and also on 10-6-86. However, he is not present today nor has he filed any statement of claim. Therefore, it appears that the workman is not interested in pursuing this dispute. Hence this reference is disposed of for non-prosecution and 'No Dispute' award is given.

G. S. KALRA, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal
New Delhi

June 25, 1986.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

June 25, 1986.

[No. L-13012/13/84-D.II(B)]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

का. आ. 2743:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-1986 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 17th July, 1986.

S.O. 2743.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(65)/1985.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Nagpur and their workmen represented through the Secretary, Food Corporation of India Employees Association, C/o Food Corporation of India, Nagpur (M.S.).

APPEARANCES :

For Union—Shri N. K. Shukla.

For Management—Shri N. Sunderam.

INDUSTRY : Food Corporation—District : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : June 27, 1986.

The Central Government vide Notification No. L-42012(53)/84-D.V. Dated 30th July, 1985 referred the following dispute, for adjudication :—

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Nagpur in terminating orally the services of 12 casual workers mentioned in Annexure below with effect from 14-8-1984 is justified ? If not, to what relief are they entitled ?"

ANNEXURE

1. Shri Suresh Jarulkar
2. Shri Ramesh Ambade
3. Shri Suresh Rakshit
4. Shri Mahendra Kamble
5. Shri Siddharth Mandape
6. Shri Pandurang Padal
7. Shri S. P. Nihare
8. Shri R. G. Kswade
9. Shri Bhaiyya Sudam
10. Shri Narendra Gaikawad
11. Shri M. B. Rana
12. Shri Baba Balekar.

2. Non controversial facts of the case are that the applicants were working as casual labourers in the Engineering Wing of the Food Corporation of India and their services were dispensed with orally with effect from 14-8-1984.

3. The case of the applicant further is that the management manipulated the attendance of the workmen applicant in such a way (by giving break in service after about 15 days of service) that the workers were not allowed to qualify the prescribed eligibility of completing 240 days in a year or 120 days in six months. They were not paid overtime though the provisions of the Bombay Shops and Establishments Act and the Minimum Wages Act apply to the management. They have also not been paid bonus and wages for national holidays in the year 1983-84. The job of the workmen in the Engineering Department was of regular and permanent naure. The management terminated the services of these 12 workmen and appointed other labourers through the Contractors which is in contravention of the following provisions :—

(a) Unfair labour practice within the meaning of item no. 10 of Schedule V of the I.D. Act ;

(b) Change within the meaning of item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV of the I.D. Act ; and

(c) the provisions of the Contract (Abolition & Regulation) Act.

4. The case of the management is that the workmen in question were working as casual labourers on "no work no wages basis". They were engaged depending on the availability of the work which were not of perennial and permanent nature. The work was of casual nature such as cleaning of gutters when they were blocked. The management employed these casual labourers when they required and when they were available. It is not true that the major civil work in Engineering Division was not being done by the Civil Contractor or it has been wrongly introduced.

5. The management has not contravened any lawful provisions and the workmen are not entitled to any relief.

6. It is the case of the workmen that the nature of work for which they were employed as casual labourers was of perennial nature. But the management employed them in such a fashion that they could not complete their statutory period of 240 days in a year. On 14-4-84 the management terminated their services orally and started getting the work done through the contractor. Thus the first act of the management amounts to unfair labour practice within the meaning of Clause 10 of Schedule V and the second act amounts to change of service conditions within the meaning of Item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV of the I.D. Act. Thus they have contravened the provisions of Sec. 9A read with item no. 9, 10 and 11 of Schedule IV clause 10 of Sch. V of the I.D. Act. In support of this plea the workmen has filed the copies of tender notice issued to the contractor and pronouncement made in the case of Workmen of Food Corporation of India Vs. M|s. Food Corporation of India (AIR 1985 SC 670). I have gone through the provisions and the authority relied on by the workmen and I find that the contention is correct that it amounts to unfair labour practice and change in service condition as alleged provided the workmen were working on perennial and not casual nature of work. In that case they would have the moved for prosecution and of punishment provided under the I.D. Act But if the nature of their employment was purely for the temporary or casual nature of work the story would be different.

7. I, therefore, proceed to examine the nature of employment of the present workmen. In support of their case only Shri Ramesh Nilkhand Ambare (W.W.1) workman has been examined. He has stated that he used to clean gutters, put tar plaster over grain, help the electric department, cut grass and do other miscellaneous work. In his cross-examination he has admitted that the grass cutting was done only for 2-3 days in a month and gutter cleaning was done once in a year. He has further stated that tar plastering was done over roofs of godown during mansoon season. He does not specify the nature of help he gave to the electric department and what was the miscellaneous work. In view of this admission and circumstance it is difficult to hold that the workmen were employed on a perennial nature of work. The work was of purely temporary and casual nature and not perennial.

8. In this connection, it is pertinent to note the following definition of 'workman' given in the 1st Schedule to the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 :—

"2(e) A "temporary" workman is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period.

(f) A "casual" workman is a workman whose employment is of a casual nature."

As pointed out from the evidence above the work for which the applicants were employed was of temporary nature and they were admittedly casual workmen. Therefore they come under the above definition.

9. It is the admitted case of the applicants themselves that they did not work for 240 days in a year. Therefore they cannot swim into the harbour of Section 25F of the I.D. Act as has also been held by the Presiding Officer of New Delhi in D.O. No. 150|81 dated 17th August, 1983.

10. It has been contended as a last resort that the management employed so many casual labour and made them permanent which amounts to discrimination. Simply because others have been treated differently it does not give the right to the applicants to insist that they be re-employed or absorbed as permanent workmen as of right. Looking to the nature of their employment, as already pointed out had they been employed on a work of perennial nature their rights would have been protected.

11. In view of my finding above, I answer the reference as under :—

That the action of the management of Food Corporation of India, Nagpur in terminating orally the services of 12 casual workers mentioned in the Annexure to the reference order (named above) with effect from 14-8-1984 is justified and the 12 workmen are not entitled to any relief. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer.

27-6-1986

[No. L-42012|53|84-D.V.]

का. आ. 2744.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, नार्दन रेलवे के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-86 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2744.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th July, 1986.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 45|86

In the matter of dispute between :

Shri R. K. Mahajan through The Assistant General Secretary, Uttar Railway Karamchari Union, 5239, Ajmeri Gate, New Delhi.

VERSUS

The General Manager,
Northern Railway, Baroda House,
New Delhi.

APPEARANCES :

None for both sides.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide notification No. L-41012(39)|85-D.II(B) dated 18-3-1986 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Senior Personntl Officer, Head Quarters, Northern Railway in dropping out name of Shri R. K. Mahajan from the confirmation list of Clerks, is justified. If not to what relief Shri Mahajan is entitled to ?"

2. Notices of the reference were sent to the parties. The workman had put in appearance through Shri Yogeshwar Dutt on 7-5-86 and also on 11-6-86 he appeared in person. However, he is not present today nor has he filed any statement of claim. Therefore, it appears that the workman is not interested in pursuing this dispute. Hence this reference is disposed of for non-prosecution and 'No dispute' award is given.

Further it is ordertd that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

June 27, 1986

[No. L-41012|39|85-D.II(B)]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का. आ. 2745.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-7-86 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2745.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th July, 1986.

BEFORE SHRI G.S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 38|83

In the mattter of dispute between :

Shri Yoginder Sharma through

General Secretary, All India joint Council of Food Corporation of India Employees Union and All India Food Corporation Executive Employees Federation, Q. No. 560, Sector V, R. K. Puram, New Delhi.

VERSUS

The Managing Director, Food Corporation of India, 16-20 Barakhamba Lane, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri S. K. Charchara for the workman.

Shri Ashwani Kumar for the Management.

AWARD

The central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-42011|31|81-FCI-D.IV(A) has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in transferring Shri Yoginder Sharma, Chairman, Joint Action Committee, Naraina Depot is fair and justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. Notices were issued to the parties and the parties appeared and filed their claim statement and written statement. Today the parties have filed a written settlement and the workman do not want to pursue with the reference any more. Hence a 'No Dispute' Award is given in terms of settlement. The reference is disposed of accordingly.

Further ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

July 3, 1986.

[No. L-42011|31|81-FCI|D.IV(A)|D-II B]

का. आ. 2746.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-7-86 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2746.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Food Corporation of India (PO), Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th July, 1986.

BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD, B.Sc. B. L, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

(Constituted by the Central Government)
Wednesday, the 25th day of June, 1986

Industrial Tribunal No. 89 of 1985

[In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Food Corporation of India, Madras-8.]

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary, Madras Port United Labour Union, 'Bhagat House', 204, Pra-Kasam Salai, Broadway Madras-8.

AND

The Joint Manager, (PO), Food Corporation of India, Chennai House, Esplanade, Madras 8.

REFERENCE :

Order No. L-42012(9)|85-D.V., dated 10-12-1985 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the refernence and other connected papers on record and upon hearing of Thiru P. B. Krishnamurthy, Advocate appearing for the Management and the Union being absent, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workmen and the Management of Food Corporation fo India, Madras-8 arising out of a reference under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-42012(9)|85-D.V., dated 10-12-1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issues :

(a) Whether the action of Food Corporation of India in relating to the establishment of Joint Manager (Port Operations) Food Corporation of India, Madras Port, Madras-600011 in denying wages to Shri P. Dhanakoti, WCL No. 140 for the period of suspention from 31-2-1983 to 29-4-1983 is justified. If not, to what relief the workman concerned is entitled

(b) If the answer of (a) is affirmative then, whether the management is justified and legal in denying the subsistance allowance to the worker concerned for the period of his suspension from 31-3-1983 to 29-4-1983 ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

(2) Summons were isued for appearance of parties and filing claim statement. Union and the Management were represented by counsel.

(3) Today, when the dispute was called, Union was absent and no representation was made on its behalf. No claim statement was filed. Hence the claim of the workmen is dismissed for default. No costs.

Dated, this 25th day of June, 1986.

FYZEE MAHMOOD, Industrial Tribunal

[No. L-42012|9|85-D.V|D.II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1986

आदेश

का.आ. 2747 :—भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 461 दिनांक 5 फरवरी, 1963 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, जिसका मुख्यालय मद्रास में स्थित है, के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो गया है ;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार थिरु टी. वी. ए. अब्दुल समद को पूर्वोक्त गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं. एम.-11020/7/81-डी. 1(ए)]

शशि भूषण, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 1986

ORDER

S.O. 2747.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Madras constituted by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 461 dated the 5th February, 1963.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Thiru T. V. A. Abdul Samad as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11020|7|81-D.I (A)]

SHASHI BHUSHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1986

का.आ. 2748 :—चूना पत्थर और डोलामाइट खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1973, के नियम 3 के उप-नियम (2) के साथ पठित चूनापत्थर और डोलामाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक सलाहकार समिति गठित करती है, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, 555-ए/2, न्यू ममफोर्ड गंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष (पदेन)
3. प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कानपुर (उत्तर प्रदेश)	(केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि (पदेन)

4. श्री मोहम्मद असलम खां, विधायक, मुजफ्फराबाद, सहारनपुर, 75/ए, राजपुर रोड, देहरादून	उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा का सदस्य
5. श्री रवि प्रकाश, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश खनिज विकास बोर्ड, लखनऊ	चूनापत्थर और डोलोमाइट खान मालिकों के प्रतिनिधि
6. श्री सी.जी. गुजराल, 36-बी, गोर, रेसकोर्स, देहरादून	—यथोक्त—
7. श्री रामाश्रय सिंह, प्रेजीडेंट, इंटक, उत्तर प्रदेश, शाखा, 163/3/1, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., रानी पुर, हरिद्वार	चूनापत्थर और डोलोमाइट खान में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधि
8. श्री प्रदीप चक्रवर्ती, सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, भारतीय मजदूर संघ कार्यालय, जे 98 चुर्क, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	—यथोक्त—
9. श्रीमती राज आनन्द, सेक्रेटरी, देहरादून लाइमस्टोन कर्मचारी संघ, देहरादून, मार्फत अमर अकादमी, रेसकोर्स, देहरादून	महिला प्रतिनिधि
10. कल्याण प्रशासक इलाहाबाद	सेक्रेटरी

2. उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा ।

[सं. 19012/2/85—कल्याण; 2 (सी)]
एस. एस. भल्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 1986

S.O. 2748—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (61 of 1972), read with sub-rule (2) of rule 3 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Committee for the State of Uttar Pradesh consisting of the following members, namely :—

1. Labour Minister Government of Uttar Pradesh.	Chairman
2. Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation 555-A/7, New Mumfordganj, Allahabad (U.P.)	Vice-Chairman (Ex-officio)
3. Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur (U.P.)	Central Government representative Ex-officio)
4. Shri Mohammad Aslam Khan Member Legislative Assembly, Muzaffrabad, Saharanpur. 75/A, Rajpur Road, Dehradun.	Member of the Legislative Assembly of the State of U.P.
5. Shri Ravi Prakash, Managing Director, Uttar Pradesh Mineral Development Board, Lucknow.	Represents the Limes Dolomite Owners.
6. Shri C.G. Gujeral, 36-B, Govind Nagar, Race Course, Dehradun.	—
7. Shri Ramyash Singh, President INTUC, U.P. Branch. 163/3/1 BHEL, Ranipur. Haridwar.	Representatives of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.
8. Shri Pradeep Chakravarty, Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh U.P. Office Bhartiya Mazdoor Sangh. J-98 Churck, Mirzapur, U.P.	—
9. Smt. Raj Anand, Secretary, Dehradun Limestone Karamchari Sangh Dehradun, C/0 Amar Academy Racecourse, Dehradun.	Woman representative.
10. Welfare Administrator, Allahabad.	Secretary.

2. The headquarters of the said Advisory Committe shall be at Allahabad.

[Go. 19012/2/85-W-II (c)]
S.S. BHALLA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986